



माँ दुर्गा ज्वेलर्स

सोने एवं चांदी के आभूषणों के विक्रेता

उचित व्याज में गिरवी रखी जाती है।

शॉप नं.-69, सी-नाकेंट, सेक्टर-6, गिलाई

मो.-9424124911

खास-खबर

ठाणे में शिवसेना यूबीटी नेता की हत्या, पहले मारपीट फिर चलाई गोली

ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना (यूबीटी) के नेता प्रदीप पूर्णकर की मंगलवार को मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, कुछ हमलावरों ने कथित तौर पर उन पर हमला किया और गोलीबारी की। हमले में घायल होने के बाद प्रदीप पूर्णकर की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना के नेता प्रदीप पूर्णकर पर दो राउंड गोलियां चलाई गईं। गोलीबारी में घायल होने के बाद पूर्णकर की हालत गंभीर हो गई। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि, प्रदीप पूर्णकर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पूर्णकर को कपूरबावड़ी थाने के अंतर्गत आर मॉल के पास स्थित इन्फिनिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रदीप पूर्णकर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

जालंधर में अमित शाह की रैली से पहले धमकी

जालंधर। पंजाब के जालंधर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली से पहले कई स्कूलों को एक धमकी भरा ईमेल भेजे जाने का मामला सामने आया है। ईमेल में रैली स्थल, बसों और श्री देवी तालाब मंदिर समेत अलग-अलग स्थानों पर आईईडी/बम धमाके करने जैसी धमकियां दी गई हैं। संदेश में बच्चों को स्कूल भेजने और रैली में जाने को लेकर भी चेतावनी दी गई है। ई-मेल में लिखा है कि रैली के स्टेज के नीचे आईईडी रखा है। स्कूल-मंदिर और कोर्ट को उड़ा देंगे। 100 बसों में से 2-3 बसों में बम फिट किए हैं। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। ईमेल बुधवार तड़के 7:50 पर आया, जिसकी सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं।

बगहा में बांध टूटी, डूबे सैकड़ों घर, गांव बने टापू

बेतिया। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी के उफान ने तबाही मचा दी है। बगहा, बैरिया और योगापट्टी प्रखंडों के निचले इलाकों में नदी का पानी तेजी से फैलने से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। वाल्मीकिनगर विधानसभा क्षेत्र के मधुबनी प्रखंड अंतर्गत चिरइही पंचायत के सैकड़ों घर पानी से घिर चुके हैं। बाढ़ की मार झेल रहे ग्रामीणों के बीच सुरक्षित ठिकानों की तलाश को लेकर भारी चिंता बनी हुई है। जबकि, वाल्मीकिनगर गंडक बराज से डिस्चार्ज घटकर रात 8 बजे 1,55,600 क्यूसेक दर्ज किया गया है।

इधर पड़ा आईटी का छापा उधर लंदन में बीमार पड़े मगनानी मुंबई। बॉलीवुड के जाने-माने प्रोड्यूसर वाशु भगनानी की तबीयत बिगड़ गई है, वह इस वक्त लंदन में हैं और उन्हें वहीं एक अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब दो दिन पहले सोमवार, 28 सितंबर को मुंबई आयकर विभाग ने वाशु और उनकी एक?ट्रेस बहू रकुल प्रीत सिंह से जुड़े 12 ठिकानों पर एकसाथ छापेमारी की है। जांच अधिकारियों का मानना है कि फिल्म प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के नाम पर कथित तौर पर विदेश में पैसा भेजा जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह सर्च ऑपरेशन टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में है।

दहेज के लिए विवाहिता को फंदे से लटकाया, बेटियां पैदा होने पर की हत्या, पति समेत तीन गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। जिले में दहेज के लालच और लगातार दो बेटियां पैदा होने के बाद एक नवविवाहिता की गला घोटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद वारदात को छिपाने के लिए आरोपियों ने मृतका के शव को फंसी के फंदे पर लटका दिया, ताकि पूरा मामला खुदकुशी जैसा दिखाई दे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मृतका के पति, देवर और सास को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार सकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सकरी की रहने वाली दुर्गा निर्मलकर (26) का विवाह वर्ष 2022 में ग्राम सैदा निवासी रोहित निर्मलकर



(30) के साथ हुआ था। शादी के बाद दुर्गा ने दो बेटियों को जन्म दिया। मायके पक्ष के अनुसार दूसरी बेटी के जन्म के बाद से ही ससुराल वाले उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे और लगातार उस पर मायके से 1 लाख 65 हजार रुपये लाने के लिए दबाव बना रहे थे।

मारपीट के बाद गला घोट्टा

26 सितंबर को ससुराल में विवाद के दौरान आरोपियों ने दुर्गा की

श्रीकंचनपथ



■ नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के अंतर्गत दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए विशेष कार्यक्रम हर्षित अग्रवाल

रायपुर। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के अंतर्गत प्रेरणा गुरुकुलम विद्यापीठम्, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हीरापुर, रायपुर में दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल शामिल हुए। उन्होंने छात्राओं से संवाद करते हुए उनके आत्मविश्वास, प्रतिभा और योग प्रदर्शन की सराहना की।

संजय अग्रवाल ने कहा कि ये दृष्टिबाधित नहीं हैं, इनके पास दिव्य दृष्टि है। इनके भीतर जो प्रतिभा, टैलेंट और कला है, वह हर किसी के पास नहीं होती। उन्होंने कहा कि प्रेरणा गुरुकुलम विद्यापीठम् वर्षों से ऐसी बेटियों को तैयार करने का काम कर रहा है, जो आज अलग-अलग क्षेत्रों में आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ा रही हैं।

उन्होंने कहा कि यहां छात्राओं को केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि कंप्यूटर प्रशिक्षण, किचन से जुड़े कार्य, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता से जुड़े विभिन्न कार्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि

बेटियां देश के अलग-अलग हिस्सों में अपनी प्रतिभा और क्षमता के दम पर आगे बढ़ें और अपने साथ-साथ प्रदेश का नाम भी रोशन करें।

योग आयोग को आज अपने ब्रांड एम्बेसडर मिल गए

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं द्वारा हास्य योग सहित विभिन्न योग क्रियाओं का शानदार प्रदर्शन किया गया। छात्राओं ने एक साथ, एक लय और अनुशासन के साथ योगाभ्यास प्रस्तुत किया। इस प्रदर्शन से प्रभावित होकर संजय अग्रवाल ने कहा कि सामान्य बच्चों के योगाभ्यास के दौरान अक्सर प्रशिक्षक उन्हें लगातार आसनों के लिए निर्देशित करते दिखाई

देते हैं, लेकिन यहां छात्राओं ने बिना किसी दृश्य सहायता के एक साथ एक लय में योग करके सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने कहा हम हर चीज के ब्रांड एम्बेसडर खोजते हैं, लेकिन आज मुझे योग आयोग के ब्रांड एम्बेसडर मिल गए हैं। ये बच्चे ही योग आयोग के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। मैं इसकी घोषणा करता हूं।

40 वर्षों की साधना प्रेरणादायी

संजय अग्रवाल ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सामान्य बच्चों को भी लंबे समय तक संभालना और उनका मार्गदर्शन करना आसान नहीं होता। ऐसे में लगातार 40 वर्षों से दृष्टिबाधित बच्चों के जीवन को संवारने, उन्हें शिक्षित करने, प्रशिक्षित करने और आत्मनिर्भर

भोपाल में रिटायर्ड आईएसएस राकेश अग्रवाल का मर्डर, नौकर फरार

भोपाल। भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र के सूरजनगर इलाके में एक रिटायर्ड आईएसएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की उनके ही घर के भीतर गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। रिटायर्ड आईएसएस अधिकारी अपनी पत्नी के साथ इस मकान में रहते थे। हत्या घर के अंदर ही की गई। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि हत्या के असली कारणां और वारदात के पीछे की परिस्थितियों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगा। बहरहाल, पीड़ित परिवार ने महज दो दिन पहले ही एक नए नौकर को काम पर रखा था, जो इस घटना के बाद से ही लापता है।

जब आंखें बंद होती हैं, तब भगवान के दर्शन होते हैं

संजय अग्रवाल ने छात्राओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इन बेटियों को दृष्टि भले ही कम दी हो, लेकिन उन्हें ऐसी दिव्य दृष्टि दी है, जिसके माध्यम से वे दुनिया को अपने अलग अंदाज में पहचान और समझ पाती हैं। उन्होंने कहा कि जब हम भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं और कोई पूछता है कि कहाँ जा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन भगवान के सामने पहुंचते ही हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि जब आंखें बंद होती हैं, तभी भगवान के दर्शन होते हैं और इन बच्चों को भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। कार्यक्रम में आर. वाय. तिवारी, अध्यक्ष शाला समिति, डॉ. राकेश कामरान, सचिव, दलजीत बग्गा, भवन निर्माण समिति, संजीव बसंत, कोषाध्यक्ष, बिंदु बग्गा, सदस्य, रामगणि शुक्ला, पतंजलि रायपुर, रविकांत कुंभकार पर्यवेक्षक अधिकारी तथा अनिल जैन, संस्था अध्यक्ष सहित अन्य गणमान्यजन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।



बनाने का कार्य करना अपने आप में बड़ी साधना है। उन्होंने कहा कि प्रेरणा गुरुकुलम जैसी संस्थाएं केवल बच्चों को शिक्षा देने का काम नहीं कर रही, बल्कि उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक और आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए तैयार कर रही हैं। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं के उत्साह,

अनुशासन और योग प्रदर्शन ने उपस्थित लोगों को प्रभावित किया। संजय अग्रवाल ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रतिभा किसी दृष्टि की मोहताज नहीं होती, अवसर और विश्वास मिलने पर यही प्रतिभा दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाती है।

भारतीय तटरक्षक बल की बड़ी कार्रवाई ईरानी नाव से 3000 करोड़ की ड्रस जब्त

■ पांच पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार

मुंबई। भारतीय तटरक्षक बल ने अरब सागर में ड्रस तस्करी की एक बड़ी कोशिश नाकाम की है। लक्षद्वीप के पश्चिम में समुद्र में कार्रवाई करते हुए एक ईरानी जहाज (धो) को पकड़ा गया। जहाज पर पांच पाकिस्तानी नागरिक सवार थे। तलाशी के दौरान 526 किलोग्राम हेरोइन और मेथामफेटामाइन बरामद किया गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 3,000 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है।

भारतीय तटरक्षक बल के मुताबिक, यह कार्रवाई गुजरात एंटी-टेरिस्म स्कॉड के साथ मिलकर की गई। समुद्र और हवा से निगरानी के जरिए संदिग्ध जहाज की लगातार ट्रैकिंग की गई। इसके बाद 25 सितंबर को तटरक्षक बल ने उसका पीछा किया और जहाज पर सवार होकर तलाशी ली।

कोस्ट गार्ड ने बताया कि कार्रवाई के दौरान संदिग्ध ईरानी धो, उसके चालक दल और जब्त किए गए मादक पदार्थों को हथियारबंद सुरक्षा के बीच मुंबई लाया गया है। यहां विभिन्न एजेंसियां मिलकर



आरोपियों से पूछताछ करेंगी और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

526 किलो हेरोइन और मेथाम फेटामाइन बरामद

तटरक्षक बल के अनुसार, जब्त किए गए मादक पदार्थों में हेरोइन और मेथामफेटामाइन शामिल हैं। एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह खेप कहाँ से लाई गई थी और इसे कहाँ पहुंचाया जाना था। तटरक्षक बल ने कहा कि समुद्री निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर की गई इस कार्रवाई से भारत के समुद्री क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर नजर रखने की क्षमता का पता चलता है।

लिव-इन में चाची हुई गर्भवती तो उसे मारकर हनुमान दर्शन के लिए निकल गया भतीजा

जयपुर ए। जयपुर के बिंदायका थाना इलाके की प्रेस्टीज गाडन कॉलोनी में 20 साल के एक युवक ने अपनी ही गर्भवती चाची की बेरहमी से हत्या कर दी। शव को दफना दिया और सामोद हनुमान जी के दर्शन के लिए पदयात्रा पर निकल गया।

बिंदायका थानाधिकारी अनिल कुमार जैमिनी के अनुसार, मृतका किरण रावत बाराबंकी से थी जबकि आरोपी प्रवेश कुमार रावत मृतका के गांव का ही रहने वाला है। किरण उसकी चाची लगती थी। गांव में प्रेम-प्रसंग पनपने के बाद दोनों सामाजिक बंदिशों को तोड़कर जयपुर आ गए थे और



बिंदायका की प्रेस्टीज गाडन कॉलोनी में किराए का मकान लेकर लिव-इन पार्टनर के रूप में साथ रह रहे थे।

पुलिस पूछताछ में आरोपी प्रवेश ने बताया कि उसे किरण के किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध होने का शक हो गया था। इसी शक के चलते 23 सितंबर को

दोनों के बीच कहासुनी हुई। गुस्से में आकर प्रवेश ने किरण का गला घोट दिया और मुंह पर कपड़ा दबाकर उसकी हत्या कर दी। किरण गर्भवती थी, लेकिन हैवानियत में अंधे हो चुके प्रवेश ने रहम नहीं दिखाया और शव को छिपाने के लिए मकान के चौक में गहरा गड्ढा खोदा तथा लाश को दफनाकर ऊपर से मिट्टी ढाल दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हनुमान भक्ति का ढोंग रचाने सामोद की पदयात्रा पर निकल गया। 24 से 26 सितंबर तक वह रोजाना की तरह अपनी फैक्ट्री में काम करता रहा, ताकि किसी को जरा सा भी शक न हो।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: बंद निगमों के कर्मचारियों को मिलेगा एक-एक लाख मुआवजा, तीन महीने में भुगतान के निर्देश

नईदिल्ली ए। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार और झारखंड सरकार को राज्य के स्वामित्व वाले पांच बंद हो चुके निगमों के संबंधित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और मजदूरों को एकमुश्त एक-एक लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने दोनों राज्यों को ब्याज सहित संपूर्ण भुगतान तीन महीने के भीतर करने का आदेश दिया है। इस आदेश से 600 से अधिक कर्मचारियों और कामगारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की बात सामने आई है। संबंधित मामला बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 लागू होने के बाद राज्य के स्वामित्व वाले पांच बंद पड़े निगमों के कर्मचारियों की देनदारियों और सेवा संबंधी बकाये के बंटवारे से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट



के आधिकारिक रिकॉर्ड में यह मामला बिहार राज्य अर्ध सरकारी अराजपति कर्मचारी महासंघ बनाम बिहार राज्य, W.P.(C) No. 932/2022 के रूप में दर्ज है।

सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने बिलंब से दिए जाने वाले कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के बकाये पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, देरी से भुगतान किए गए वेतन, मजदूरी और अन्य मौद्रिक

बकाये पर छह प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा। ब्याज की गणना प्रत्यक्ष देय होने की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान किए जाने की तारीख तक की जाएगी।

चार हफ्ते में कर्मचारियों की जानकारी करें सार्वजनिक

प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र अदालत ने बिहार और झारखंड सरकार को चार हफ्ते के भीतर सभी संबंधित कर्मियों और कामगारों की अद्यतन जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। यह विवरण दोनों राज्यों के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक विभागों की आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रकाशित करना होगा।



अब हर नज़र आपके Brand पर !

www.harshmediaadvertisers.com

info.harshmedia@gmail.com

harsh_media_advertisers

8253029444 | 8435918888

- Unipoles / Hoarding
 - Outdoor LED Screen
 - Digital LED Television
 - Train Wrap Branding

- Mobile LED Vehicle
 - Social media Advt.
 - News Paper advt.
 - Branding consultancy

संपादकीय

महिला सुरक्षा का संकट

जवाबदेही के बिना योजनाओं का कोई अर्थ नहीं

यह हमारे लोकतंत्र की विडंबना है कि कार्यपालिका की लचर कार्यशैली के चलते गाढ़े-बगाहे न्यायालय को उन मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ता है, जिनका दायित्व निभाना सरकारों का काम है। वैसे कहने को तो पूरे देश में महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिये तमाम कायदे-कानून बनाए गए हैं। लेकिन जब इन कानूनों व योजनाओं को हकीकत में अमलीजामा पहनाने की बात सामने आती है तो जवाबदेही का अंतर साफ नजर आता है। हाल के दिनों में दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्म के मामलों पर स्वतः संज्ञान लेकर शीर्ष अदालत ने इस कड़वी हकीकत

“ हाल के दिनों में दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्म के मामलों पर स्वतः संज्ञान लेकर शीर्ष अदालत ने इस कड़वी हकीकत को उजागर कर दिया। इन मामलों में शीर्ष अदालत ने सिर्फ यही नहीं पूछा कि ये संगीन अपराध क्यों हुए, बल्कि यह भी जानना चाहा कि इन अपराधों को रोकने के लिये बनाया गया सिस्टम क्या हकीकत में कुछ काम करता है? कोर्ट का सवाल था कि क्या वास्तव में आपातकाल में मदद करने वाली हेल्पलाइन तुरंत जवाब देती है? क्या सीसीटीवी कैमरे पूरी मुसंदी के साथ काम कर रहे हैं? क्या महिलाओं के लिये असुरक्षित समझी जाने वाली जगहों को पहचान करके वहां पैट्रोलिंग की जाती है? क्या महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिये बने डेटाबेस, महिलाओं के लिये हेल्प डेस्क और जांच करने में मददगार ट्रैकिंग सिस्टम का कारगर तरीके से प्रयोग हो रहा है? शीर्ष अदालत का यह सवाल तार्किक है कि जब ये सिस्टम फेल हो जाता है तो विफलता के लिये किसी की जवाबदेही तय की जाती है? निस्संदेह, अदालत ने तंत्र की दुखती रग पर हाथ रखा है। सही मायने में ये सवाल हर किसी को परेशान करने वाले हैं। यह हकीकत है कि देश में नये-नये सुरक्षा कार्यक्रमों की घोषणा

करने, पोर्टल, हेल्पलाइन और कर्मेटियां बनाने में तो कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी समस्या के निस्तारण के लिये कोई सिस्टम या मैकेनिज्म बना देना ही कर्तव्यों की इलश्री मान लिया जाए?

उल्लेखनीय है कि अक्सर आम लोगों द्वारा शिकायत की जाती रही है कि सुरक्षा की दृष्टि से संवेदशील सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं होती, सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से काम नहीं कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर इस बाबत की गई शिकायतें अक्सर फाइलों में उलझकर रह जाती हैं। कहने को ऐसे अपराधों को रोकने वाला सिस्टम फाइलों में तो दर्ज होता है, लेकिन जब वास्तव में किसी व्यक्ति को इसकी जरूरत होती है, तो यह हमेशा की तरह नदारत मिलता है। ऐसे में देश की शीर्ष अदालत द्वारा सुरक्षा उपायों के ऑडिट, व्यवस्था की कमजोरियों की पहचान, किसी घटना के होने पर प्रतिक्रिया देने के समय और कार्यक्षमता के मूल्यांकन पर जोर देना, एक स्वागत योग्य कदम ही कहा जायेगा। सही मायने में ऐसे मामलों में सिर्फ पुलिस को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। ऐसे में सड़कों में स्ट्रीट लाइट न होने पर म्युनिसिपल एजेंसियां, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, प्रशासक, तकनीक उपलब्ध करने वाले विभाग और न्याय व्यवस्था आदि सभी सुरक्षा शृंखला का हिस्सा हैं। निर्विवाद रूप से किसी भी एक स्तर पर विफलता के गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। दिल्ली के बहुचर्चित निर्भया प्रकरण के चौदह साल बाद मिला यह सबक स्पष्ट करता है कि कानून और योजनाएं तो बस शुरुआत मात्र हैं। असली कसौटी तो उनके लागू होने में है। इस आलोक में किसी पार्क में जाने, बस में चढ़ने या घर पैदल जाने वाली किसी महिला को इस बात पर आशंकित नहीं होना चाहिए कि किसी संकट की स्थिति में सुरक्षा के लिये बना सिस्टम काम करेगा भी या नहीं। निस्संदेह, किसी भी नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है। सही मायने में यही जवाबदेही ही उस जिम्मेदारी को हकीकत बनाती है। विश्वास किया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद शासन-प्रशासन महिला सुरक्षा की गंभीर चिंता को संवेदनशील ढंग से महसूस करेंगे। तभी संकट के समय महिलाएं आश्वस्त हो सकेंगी कि सिस्टम उनकी मदद के लिये तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के लिए आगे आएगा।

मरीज के भरोसे का सौदा करने पर हो सरख्ती

इन्दु भुषण

अस्पतालों को निवेश करने, नए इलाज और वाजिब मुनाफा कमाने की व्यापारिक आजादी होनी चाहिए। लेकिन इस आजादी का मतलब यह नहीं हो सकता कि आईसीयू बिस्तर पर पड़े मरीज का आर्थिक शोषण किया जाए।

जैसे ही कोई मरीज अस्पताल में भर्ती होता है, व्यवसाय के मानक नियम पूरी तरह भंग हो जाते हैं। स्ट्रेचर पर लेटे घबराए मरीज के पास न तो इलाज के दाम की तुलना करने का समय होता है और न ही मोल-भाव करने की शक्ति। वे अनिश्चितता के असामान्य स्तर को स्वीकार कर लेते हैं, यह यकीन करते हुए कि जो इलाज सुझाया जा रहा है, वह जरूरी है और उसका दाम वाजिब है। जब अस्पताल इस मजबूरी का फायदा उठाकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने लगे, तो यह उस भरोसे को बुरी तरह ध्वस्त करने जैसा है।

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन का हालिया सर्वे इस समस्या की भयावहता को उजागर करता है। पड़ताल करने वालों ने पाया कि इंटरवेनस (आईवी) इन्स्यूजन सेट की जो लागत अस्पताल को 11.05 रुपये पड़ती है, उसका दाम मरीज से 325 रुपये वसूला गया—यानी 2,841 प्रतिशत अधिक। 29.41 रुपये में खरीदे गए कैथेटर का अधिकतम खुदरा मूल्य 310 रुपये वसूला गया, जो 954 फ़ीसदी अधिक है। कई तरह के आवश्यक मेडिकल सामानों पर कीमतें बहुधा 2,841 प्रतिशत तक ज्यादा पाई गईं। खाद्य एवं औषधि आयुक्त तुकाराम मुंडे ने डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को पत्र लिखकर केंद्रीय समीक्षा और स्पष्ट नियमों की मांग की है, ताकि खरीद दाम और घोषित अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच कितने अंतर की अनुमति हो, यह तय किया जा सके।

अस्पताल एक वैध वाणिज्यिक संस्था की श्रेणी में आते हैं। उनके लिए खरीद दाम, साफ-सुथरा भंडारण, पर्याप्त स्टॉक बनाए रखना और बर्बादी को लागत में जोड़ना एक जरूरत है, और वाजिब मुनाफा कमाने का हक भी है। लेकिन एक टिकाक व्यापारिक मुनाफे और मजबूर ग्राहक से ज्यादा पैसे उगाहने के बीच सीमारेखा स्पष्ट है। किसी भी अन्य उद्योग में ऐसा करने पर तुरंत ‘विश्वास-भंग’ का जुर्माना लग सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में, जहां ग्राहक बीमार और डरा हुआ होता है तथा कहीं और तुरंत जा नहीं सकता, इसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता।

हालांकि, जहां अनाप-शनाप दाम वसूलना एक परिचायी बन जाए, वहां नियामक परामर्श काफी नहीं होते। जो अस्पताल जान-बूझकर ज्यादा कीमत वसूलते हैं, उनके लिए अतिरिक्त लिया गया पैसा मरीजों को वापस लौटाना और भारी जुर्माना भरना अनिवार्य किया जाना चाहिए। बार-बार ऐसा करने वालों को दंड



स्वरूप सरकारी स्वास्थ्य बीमा पैलन से बाहर करना और निजी भुगतान नेटवर्क से कुछ समय के लिए निलंबित या फिर स्थायी रूप से काली सूची में डाल देना चाहिए।

हालांकि, हमें कुछ मेडिकल सामानों पर वसूले जाने वाले बहुत ज्यादा मुनाफे को शेष सामान्य वस्तुओं पर भी लागू मानकर, एकमुश्त सख्त दाम नियंत्रक निजाम बनाने की गलती करने से बचना होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में आवश्यक मेडिकल प्रक्रियाओं पर ‘कड़ी ऊपरी कीमत’ तय करने, तमाम स्टैंडर्ड मेडिकल ऑपरेशनों के लिए पैकेज रेट तय करने और मेट्रो शहरों के अस्पतालों के कमरों का किराया आसपास के थ्री-स्टार होटलों के कमरों के किराए के बराबर करने के लिए एक कानूनी संस्था बनाने की सिफारिश की है।

वेशक, समिति ने मरीजों की परेशानी को सही ढंग से समझा है, लेकिन उसके सुझाए गए उपायों से स्वास्थ्य तंत्र को भारी नुकसान पहुंचने का खतरा भी है। आईवी सेट एक मानकीकृत औद्योगिक उत्पाद है, जबकि क्लीनिकल देखभाल वैसी नहीं है। एक ही बीमारी वाले दो मरीजों को उम्र, दिल की बीमारी के इतिहास या सर्जरी की जटिलता के आधार पर एकदम अलग इलाज की आवश्यकता हो सकती है। बीमारी के लिए विशिष्ट विशेषज्ञता वाले अस्पताल में कई घंटों तक चलने वाली जटिल कैंसर सर्जरी की कीमत को उसी तर्क से तय नहीं किया जा सकता, जिससे प्लास्टिक कैथेटर की कीमत तय की जाती है।

जब सरकारी सख्त और तयशुदा कीमतें लागू कर देंगी, तो दो चीजें होंगी: अगर ऊपरी कीमत बहुत ज्यादा रख दी जाएगी, तो मरीजों को कोई खास बचत नहीं होगी; अगर यह सीमा बहुत कम रखी जाएगी, तो गुणवत्ता प्रभावित होगी। सेवा प्रदाता तब गुणवत्ता से समझौता करने लगेंगे, ज्यादा जोखिम वाले या जटिल मामलों को लेने से मना कर सकते हैं, छिपे हुए चार्ज जोड़ने लगेंगे या आधुनिक तकनीक में निवेश करना रोक देंगे।

गलत जानकारीयों से लड़ाई सही सूचनाओं से ही जीती जा सकती है

कुमार रोहित

एक बुजुर्ग को मेसेज मिला- आपकी पेंशन बंद होने वाली है, तुरंत लिंक पर केवाईसी करें। घबराहट में उन्होंने लिंक खोला और देखते ही देखते उनके बैंक खाते से 40 हजार रुपए निकल गए। उनके हाथ में मोबाइल था, सूचना थी, पर सच नहीं था। आज हर हाथ में मोबाइल है, पर सही सूचनाएं कितनी हैं? यही बड़ा सवाल है।

कभी सूचना सुविधा थी, आज जरूरत है। सांस की तरह अदृश्य, पर हर फ़ैसले में मौजूद। मौसम का हाल हो या मंडी का भाव, बच्चे का दाखिला हो या पेंशन का नियम- हर कदम पर सूचना चाहिए। स्मार्टफोन ने सूचना जेब में ला दी, पर जेब में सूचनाओं का होना और हाथों में सही सूचनाओं का होना एक बात नहीं। हम सूचनाओं के अकाल से निकलकर उनकी बाढ़ में आ चुके हैं।

यूनेस्को के विडहोक+30 घोषणापत्र ने सूचना को पब्लिक गुड यानी लोकहित



कहा है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 16.10.2 के तहत यूनेस्को वैश्विक निगरानी करता है। यूएन क्रॉनिकल (25 सितंबर 2025) के अनुसार आज 139 देशों में सूचना का अधिकार कानून है, जो 1990 में केवल 14 देशों में था। भारत में सूचना के अधिकार ने 2005 में नागरिकों को सवाल पूछने की ताकत दी। पर कानून

होना और उसका सरल रूप में नागरिक तक पहुंचना, अलग बातें हैं।

भारत में 90 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर हैं। डिजिटलॉकर, उमंग, जन-सूचना पोर्टलों ने फाइलों को फोन तक पहुंचाया, यह उपलब्धि है। फिर भी कई पोर्टलों पर जानकारी ऐसी कानूनी भाषा में है, जो नागरिकों को समझ नहीं आती। हर बोर्ड

अलग रास्ता बताए तो मंजिल तक पहुंचना कठिन है। चुनौती विश्वसनीयता की है।

डिजिटल दुनिया में सूचना के साथ फर्जी सूचना-स्पेम का सैलाब बढ़ रहा है। ट्रुकार्लर इनसाइट्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत में 2025 में 4,168 करोड़ स्पैम कॉल और 12,903 करोड़ स्पैम मेसेज पहचाने गए- यानी रोज औसत करीब 47 करोड़ अवांछित कॉल-मेसेज। ऐसे में दूरसंचार विभाग के ‘संचार साथी’ जैसी विनियामक पहल और पीआईबी फैक्ट चेक जैसे तंत्र जरूरी तकनीकी कवच तो हैं, पर मेसेज फॉरवर्ड करने से पहले जांचना तो हमारा ही काम है।

हर स्क्रीन पर कुछ है, पर शोर में सच पहचानना कठिन है। पहुंच का मतलब जानकारी पहुंचना नहीं, कसौटी यह है कि नागरिक उसे समझ, परख और अपने हित में इस्तेमाल कर पा रहा है या नहीं। यह पृष्ठने का सूचना-विवेक जरूरी है कि स्रोत क्या है, विश्वसनीयता कितनी है, संदर्भ क्या है आदि। सोशल मीडिया और एआई ने सूचनाओं की गति तेज तो की है, पर

तृतीय, सरकार और बीमा कंपनियां अपनी थोक क्रय शक्ति का अधिक असरदार ढंग से प्रयोग करें। ज्यादातर बहस इस बात पर होती है कि अस्पताल मरीजों से क्या चार्ज करें। हम इस बात पर बहुत कम ध्यान देते हैं कि अस्पताल और सरकारी खरीदार खुद दवाओं, डिवाइस और इम्प्लांट के लिए क्या कीमत चुकाते हैं।

थोक खरीद का अनुभव, टाटा मेमोरियल सेंटर बताता है कि बचत की कितनी बड़ी गुंजाइश रहती है। सरकारी योजनाएं करोड़ों लोगों की स्वास्थ्य देखभाल का खर्च उठाती हैं। इस विशाल क्रय शक्ति का फायदा बेहतर दाम पाने के लिए मोल-भाव करने में उठाना जाना चाहिए।

चतुर्थ, न केवल दाम, बल्कि उपयोगिता को भी नियंत्रित करें। हर सेवा की कीमत होने से अधिक कमाई करने को प्रोत्साहन मिलता है। अधिक टेस्ट, अस्पताल में ज्यादा दिन प्रवास और अतिरिक्त प्रोसीजर से ज्यादा आमदनी होती है, चाहे उससे मरीज की सेहत में सुधार हो या न हो।

अगर मरीज को जरूरत ही न हो, तो 20 फीसदी ब्रूट पर हुआ सीटी स्कैन भी बर्बादी ही है। सरकारी खरीदार और बीमा कंपनियों को असामान्य मामलों की पहचान करने के लिए क्लीनिकल पाथवे, मेडिकल ऑडिट और क्लेम एनालिटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए; मसलन, सिंजेरियन सेक्शन से बच्चे पैदा करवाने की असामान्य रूप से उच्च दर, लंबे समय तक आईसीयू में रखना, जरूरत से ज्यादा टेस्ट, जांच या किसी खास प्रोसीजर का बार-बार उपयोग। गैर-जरूरी इलाज भी इलाज के बड़े हुए खर्च का उतना ही बड़ा कारण है, जितना कि चीजों की ज्यादा कीमतें।

पंचम, गुणवत्ता को भी दाम की तरह ही साफ तौर पर दर्शाया जाना चाहिए। आज मरीजों को उन अस्पतालों के नतीजों के बारे में बहुत कम जानकारी होती है, जिन्हें वे चुनते हैं। समय-समय पर अस्पतालों को कुछ मानक पैमानों पर अपनी कार्यप्रणाली का लेखा-जोखा प्रदर्शित करना चाहिए, जैसे अस्पताल में इलाज के दौरान लगा संक्रमण, देाबरा भर्ती होने की दर, कुछ खास इलाज के परिणाम और मरीजों का अनुभव।

निःसंदेह, भारत अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत किए बिना निजी स्वास्थ्य तंत्र में कीमतों की समस्या को हल नहीं कर सकता। एक भरोसेमंद सरकारी विकल्प निजी खिलाड़ियों को सही राह पर रखता है।

अस्पतालों को निवेश करने, नए इलाज और वाजिब मुनाफा कमाने की व्यापारिक आजादी होनी चाहिए। लेकिन इस आजादी का मतलब यह नहीं हो सकता कि आईसीयू बिस्तर पर पड़े मरीज का आर्थिक शोषण किया जाए।

लेखक आयुष्मान भारत के संस्थापक पर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

डीपफेक और एल्गोरिदम के भ्रम ने उसे धुंधलाया भी है। लोकतंत्र में डिजिटल दक्ष ही नहीं, विवेकशील नागरिक भी चाहिए।

प्रशासन और नागरिक का रिश्ता 4 बातों पर टिका है : 1. पारदर्शिता- यानी सूचना सरल भाषा में, समय पर और बिना मांगे मिले, जैसे राजस्थान का जन-सूचना पोर्टल; 2. सशक्तीकरण- यानी नागरिक लाभार्थी नहीं, भागीदार बनें, जिसान अपनी भाषा में मौसम-भाव समझें; 3. भरोसेमंद शासन- यानी पहुंच के साथ निजता-सुरक्षा भी; और 4. जवाबदेही- यानी सही सूचना से सवाल और सवालों से जवाब निकलें।

हमें आज यह नहीं सोखना है कि सूचना कहां मिलेगी, बल्कि यह सोखना है कि भरोसा किस पर और क्यों करें। भविष्य के नागरिक को डिजिटल दक्षता के साथ सूचना-विवेकी भी चाहिए। विकसित भारत जीवोपी, एक्सप्रेससे या डेटा खपत से ही नहीं बनेगा, उसकी ताकत सजग नागरिक भी होंगे। हम खबरों का स्रोत जांच सकें और प्रमाण से नीतियों पर राय बना सकें, यह अब बहुत जरूरी है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

प्रहसन की राजनीति में मसखरी का अस्त्र

लोकतंत्र के मुखौटे के पीछे राजतंत्र का चेहरा छुपा है। लोकतंत्र तो खेत में डंडे के बल खड़ा बिजुका है। शब्द का मायाजाल भर है।

मन में दबी इच्छा कभी इतनी तीव्र हो जाती है कि मन की भावना निकालने के लिए आदमी गली-गली, नुकड़ और चौराहे पर कपड़े फाड़ता नजर आता है। ह्युमन नेचर है। कभी गाली देकर तसल्ली कर लेता है, कभी पत्थर चलाता है। कभी सामने वाले के घर की खिड़की-दरवाजों के कांच फोड़ देता है।

खंभा नोचने जैसी बात है। राजनीति में यह काम बिना नाम लिए किया जाता है। इस लिहाज से मसखरे का सहारा लिया जाता है। किसी बेरोजगार के लिए यह धंधा पकोड़े या भजिए तलने से ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा पब्लिसिटी भी मिलती है। ज़माना भी पब्लिसिटी का है।

सबसे सस्ता, सरल और टिकाऊ धंधा है मसखरी का। पहले भी होते थे मसखरे, पर शालीनता के साथ कॉमेडी करते थे। पर जमाने के साथ उनका रूप बदल गया। अब मसखरे नहीं कहते उन्हें। स्टैंड-अप कॉमेडियन कहा जाता है। और भाई, कॉमेडी में बोलने की पूरी आजादी है। जितना चाहो कीचड़ उछालो। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है।

परंतु मसखरे और विषय का चयन महत्वपूर्ण होता है कॉमेडी में। फिर भी मसखरे को स्टैंड-अप कॉमेडियन

कहना आजकल उसे सम्मानित करने जैसा है। और यह कार्य अंग्रेजी जैसी जेंटलमैन भाषा में आसानी से किया जा सकता है। मसखरे को बदलते दौर में मसखरा कहना उसकी शिश्खयत में पलीला लगाने जैसा है। स्टैंड-अप कॉमेडियन कहने भर से समझ लो, मसखरा सातवें आसमान पर। आसमान का तारा। आजकल सड़क से लेकर संसद तक और पब्लिक मंचों पर कॉमेडी ही ज्यादा चल रही है। अपने दिल की भड़ास निकालना हो तो एक कॉमेडियन यानी मसखरे को हायर कर स्ट्रेज पर खड़ा कर दो। जो बात खुद से नहीं कही जा रही हो, वह वाया कॉमेडियन जनता तक पहुंचा दो।

वैसे भी नेताओं के भाषण में अब कुछ सार तो बचा भी नहीं है। वही हवा, पानी, सड़क, अमीरी और गरीबी के सिवाय। कभी अडानी पर सुन लो तो कभी अंबानी पर। कभी इंदीरा पर तो कभी इलेक्शन कमीशन पर। नेता के सौ खून माफ। जो कुर्सी पर काबिज है, वह अंत तक छोड़ा नहीं चाहता। और जो सड़क पर है, वह येन-केन-प्रकारेण कुर्सी हथियाना चाहता है। लोकतंत्र के मुखौटे के पीछे राजतंत्र का चेहरा छुपा है। लोकतंत्र तो खेत में डंडे के बल खड़ा बिजुका है। शब्द का मायाजाल भर है। अपने मुंह से कुछ न कह सको तो वृक्षला जैसा कॉमेडियन तो है ही। खड़ा कर दो स्ट्रेज पर। महाभारत में भी वृहन्ला की आड़ में तोर चले थे।

रितुपुरन देव

वर्ष 2026 का अभियान तीन प्रमुख संदेशों पर आधारित है—लक्ष्णों को पहचानें, अपने दिल की रक्षा करें और जीवनशैली में समय के साथ बदलाव करें।

पिछले एक दशक में स्वस्थ हृदय के महत्व को समझने वालों की संख्या में वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन साथ ही दुखद पहलू यह भी है कि हृदय संबंधी विकारों से पीड़ित लोगों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दरअसल, गतिहीन जीवनशैली, खराब खान-पान और बढ़ता तनाव लोगों की आम दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है। इसी के चलते हृदय रोग दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक बनकर उभरा है। यह भी सही है कि जागरूकता, नियमित जांच और स्वस्थ जीवनशैली के जरिए हृदय संबंधी बहुतेरी समस्याओं को रोका जा सकता है।

स्वास्थ्य संबंधी इन्हीं सब कारणों से विश्व हृदय दिवस की परिकल्पना को साकार करते हुए एक दिन विशेष रूप से इसे पूरे विश्व में मनाने का निश्चय किया गया, ताकि लोगों को इस रोग की बारीकियों और शुरुआती लक्षणों को पहचानने में मदद मिल सके। लोगों में इतनी जागरूकता तो आए कि लोग जरूरत पड़ने पर प्राथमिक उपचार और त्वरित स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने की दिशा में जागरूक हो सकें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्व में सबसे ज्यादा मौतें हृदय रोग से होती हैं। हर साल लगभग एक करोड़ अस्सी लाख लोग इसकी वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। विश्व हृदय दिवस की



शुरुआत वर्ष 2000 में विश्व हृदय महासंघ द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से की गई। इसका उद्देश्य हृदय रोगों और उनकी रोकथाम के लिए आवश्यक उपायों के बारे में वैश्विक जागरूकता पैदा करना था। यह दिन दुनियाभर के व्यक्तियों, स्वास्थ्य संगठनों और समुदायों को हृदय स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने और निवारक उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए एक साथ लाता है। हृदय रोग के बढ़ते जोखिम और इसके कारकों को समझने, चेतावनी संकेतों को पहचानने और स्वस्थ आदतों को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई थी, जो आज सार्थक प्रतीत हो रही है। हर वर्ष यह दिन एक अलग थीम के साथ मनाया जाता है। इस बार इस दिन पर विश्व हृदय महासंघ ने ‘डोंट मिस ए बीट’ थीम रखी है,

जिसमें काफी कुछ संकेत छिपे हैं। इस संदेश को दोहराया गया है कि हृदय रोग अक्सर गंभीर जटिलताओं का कारण बनने तक अनदेखा रह जाता है।

हार्ट अटैक आने से कुछ हफ्ते पहले सीने में हल्का दर्द, अत्यधिक थकान और सांस फलने जैसे संकेत मिलने लगते हैं। एसिडिटी, सीने में हल्का दबाव, जकड़न या धीरे-धीरे महसूस होना, जो काम करने पर बढ़ता है और आराम करने पर कम हो जाता है। बिना किसी भारी काम के हर समय बहुत ज्यादा थका हुआ और कम ऊर्जा महसूस होना। सांस लेने में तकलीफ, जैसे सीढ़ियां चढ़ने या सामान्य काम करने के दौरान अचानक सांस फूलना। इसके अलावा शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द, जबड़े में जकड़न, गर्दन, पीठ, कंधे या बाएं हाथ तक दर्द का फैलना। ठंडा पसीना और बिना

सेवा संकल्प



चिरायु योजना से तरुणा को गिला स्वस्थ जीवन का उपहार

रायपुर। विकासखंड बागबहारा की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भानपुर की कक्षा 7वीं में अध्ययनरत 12 वर्षीय कुमारी तरुणा यादव को जन्मजात हृदय रोग था। विद्यालय में चिरायु दल ने तरुणा के जन्मजात हृदय रोग की पहचान की। उसे एमएमआई नारायणा हृदयालय अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उसका निःशुल्क हृदय ऑपरेशन किया गया। उपचार के दौरान परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और शासकीय स्वास्थ्य व्यवस्था के माध्यम से बच्ची को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हुई। ऑपरेशन के बाद तरुणा के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है। चिरायु दल के आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉ. विकास कुमार चौहान, डॉ. सुजाता शुक्ला, फार्मासिस्ट सुरेखा साहू एवं आरएचओ विशाखा साहू ने तरुणा की पहचान से लेकर उपचार तक की प्रक्रिया में योगदान दिया।

रसोइयों के मानदेय के लिए 117 करोड़ की मंजूरी

रायपुर। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत रसोइयों के मानदेय की टॉपअप राशि के लिए 117 करोड़ रुपये के पुनर्वित्तियोजन को प्रशासकीय स्वीकृति दी है। विभागीय आदेश के अनुसार, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का संचालन जुलाई 2026 से एसएनए-एम्सर्श के माध्यम से किया जा रहा है। इसके तहत रसोइयों के मानदेय भुगतान के लिए टॉपअप राशि के लिए पृथक से राज्य आयोजना मद में प्रावधान है। राज्य आयोजना मद में प्रावधानित राशि को केंद्र प्रवर्तित योजना के राज्याय मद में पुनर्वित्तियोजित किया गया है। आदेश में संबंधित बजट शीर्षों के बीच 102 करोड़, 10 करोड़ और 5 करोड़ रुपये के पुनर्वित्तियोजन का विवरण दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में 26 अक्टूबर से सतर्कता जागरूकता सप्ताह

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य में सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026 के भव्य और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए सभी शासकीय विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग (नई दिल्ली) के निर्देशों के अनुपालन में यह अभियान प्रदेशभर में 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक चलाया जाएगा। इस वर्ष के जागरूकता अभियान की मुख्य थीम 'सत्यनिष्ठा से समृद्धि' निर्धारित की गई है। सप्ताह के पहले दिन 26 अक्टूबर 2026 को प्रातः 11 बजे प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार के खिलाफ तथा पूरी ईमानदारी व सत्यनिष्ठा से कार्य करने की शपथ लेंगे। इस शपथ का मुख्य लक्ष्य जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार के प्रति शुच्य सहनशीलता की भावना विकसित करना और रिश्तत के लेन-देन से पूरी तरह दूर रहने का संकल्प लेना है। साथ ही नैतिक मूल्यों और कानून के शासन को मजबूत कर एक भ्रष्टाचार-मुक्त वातावरण का संदेश देना है। सप्ताह के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों की विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय सतर्कता आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

सेवा की कहानी : घर की बाड़ी में उगाई गई सब्जियों से आया परिवार के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के साथ स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य भी किया जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत खैरागढ़ जिले के ग्राम कोहलाटोला गांव की श्रीमती

तेजेश्वरी चंदेल के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। तेजेश्वरी चंदेल, ओम साईं स्व सहायता समूह, फुलवारी ग्राम संगठन एवं विद्या संकुल संगठन से जुड़ी हैं। वे अपने पति ऋग्वेद चंदेल के साथ कृषि एवं सब्जी उत्पादन का कार्य करती हैं। पहले वे सिकल सेल एनीमिया की समस्या से परेशान थीं। कमजोरी और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण उपचार पर खर्च भी करना पड़ता था।



इसी बीच एफएनएचडब्ल्यू मास्टर ट्रेनर के माध्यम से तेजेश्वरी को संतुलित आहार, पौष्टिक भोजन तथा आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाले रेडी-टू-ईट खाद्य पदार्थों के उपयोग की जानकारी मिली। कृषि सब्जी के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने घर में पोषण बाड़ी तैयार की। अब पोषण बाड़ी में उगने वाली ताजा हरी एवं मौसमी सब्जियां उनके परिवार के भोजन का नियमित हिस्सा

हैं। भोजन में पोषण और विविधता बढ़ी है तथा सब्जियां खरीदने पर होने वाला खर्च भी कम हुआ है। नियमित पौष्टिक आहार से तेजेश्वरी के स्वास्थ्य में भी सुधार आया है। तेजेश्वरी का बेटा पहले कमजोर और अक्सर बीमार रहता था। उन्होंने बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र भेजना शुरू किया। यहां बच्चे को ताजा एवं गर्म पौष्टिक भोजन, नियमित वजन जांच और टीकाकरण की सुविधा मिल रही है।

पारस पोर्टल से योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग विकास कार्यों का क्रियान्वयन हुआ तेज : साय

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। पारस पोर्टल के माध्यम से योजनाओं एवं विकास कार्यों की नियमित निगरानी के साथ विभागों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है, ताकि क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं की समय रहते पहचान कर उनका त्वरित समाधान किया जा सके।



मुख्यमंत्री श्री साय मंत्रालय महानदी भवन में पारस पोर्टल के माध्यम से आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विभिन्न विभागों के मान्यता प्राप्त योजनाओं, अधोसंरचना परियोजनाओं और जनसेवाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टरों से योजनाओं की जमीनी स्थिति की जानकारी ली तथा निर्धारित लक्ष्यों को समय-सीमा में प्राप्त करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पारस पोर्टल का उद्देश्य केवल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना नहीं, बल्कि उन कारणों की पहचान कर समाधान सुनिश्चित करना भी है, जिनके कारण कोई परियोजना या योजना अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा

रही है। राज्य स्तर से लेकर जिलों तक सभी अधिकारी इसे परिणाम आधारित प्रशासन के प्रभावी माध्यम के रूप में उपयोग करें। एग्रीस्टैक में कोई भी पात्र किसान पंजीयन से न रहे वंचित मुख्यमंत्री श्री साय ने एग्रीस्टैक में प्रत्येक पात्र किसान का शत-प्रतिशत पंजीयन निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि एग्रीस्टैक को केवल धान खेती से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यह किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ अधिक सरलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण आधारभूत व्यवस्था है।

मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि जिलों में विशेष अभियान चलाकर एग्रीस्टैक तथा डीसीएस से संबंधित लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाए। प्रत्येक वास्तविक किसान का पंजीयन सुनिश्चित हो और किसी पात्र किसान को धान विक्रय अथवा शासन की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष व्यवस्था के प्रारंभिक चरण में सामने आई व्यावहारिक कठिनाइयों से सीख लेते हुए इस वर्ष पहले से ही सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को लापरवाही के कारण यदि कोई पात्र किसान लाभ से वंचित होता है तो उसकी

जवाबदेही तय की जाए।

मुख्यमंत्री ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण की जिलेवार प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अपेक्षाकृत पीछे चल रहे जिलों को निर्धारित समय-सीमा में सर्वेक्षण पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में लापरवाही अथवा अपेक्षित सहयोग नहीं करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

बाढ़ प्रभावित परिवारों तक शीघ्र पहुंचे राहत और सहायता

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश में विगत दिनों हुई भारी बारिश और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति तथा संचालित राहत कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि भारी बारिश से प्रदेश के 17 जिलों के 500 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं और बस्तर संभाग के जिलों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ा है। प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को जनहानि, मकानों, पशुधन, अनाज तथा अन्य संपत्तियों को हुई क्षति का सर्वेक्षण शीघ्र पूरा करने और पात्र प्रभावित परिवारों तक सहायता राशि यथाशीघ्र पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षति के आकलन से लेकर सहायता राशि प्रदान करने तक की प्रक्रिया संवेदनशीलता और तत्परता के साथ पूरी की जाए।

मुख्यमंत्री ने राहत शिविरों एवं स्वास्थ्य शिविरों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मिले गति

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में और तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह योजना परिवारों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री ने वैंडर्स की संख्या बढ़ाने, सोलर दीदियों को प्रोत्साहित करने तथा हितग्राहियों के लिए ऋण को सुगम बनाने के निर्देश दिए। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सब्सिडी का अधिक से अधिक पात्र परिवार लाभ उठा सके, इसके लिए जिलों में व्यापक जागरूकता और प्रभावी क्रियान्वयन दोनों आवश्यक हैं।

सड़क और पुल के लंबित कार्यों की बाधाएं दूर करें

मुख्यमंत्री श्री साय ने लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत संचालित सड़क, पुल एवं पुलिया निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि बेहतर सड़क संपर्क सीधे आम नागरिकों की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय विकास से जुड़ा हुआ है। उन्होंने लंबित कार्यों और उनके कारणों की परियोजनावार जानकारी ली तथा संबंधित कलेक्टरों का भूमि संबंधी प्रकरणों और जिला स्तर पर लंबित अन्य प्रक्रियाओं का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों एवं प्रमुख मार्गों से जोड़ने वाली स्वीकृत सड़कों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।

पंचायतों में आधारभूत अधोसंरचना को दें प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री साय ने विकसित भारत जी-रामजी योजना की समीक्षा करते हुए ग्राम पंचायतों में आधारभूत अधोसंरचना से जुड़े आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि गांवों में बुनियादी अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण ग्रामीण अर्थव्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने स्वीकृत कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

सेवा सेतु और सीएम हेल्पलाइन को प्राथमिकता दें

मुख्यमंत्री श्री साय ने सेवा सेतु और सीएम हेल्पलाइन से संबंधित प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं, शिकायतों और आवेदनों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुशासन की महत्वपूर्ण कसौटी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोगों को छोटी-छोटी सेवाओं और समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

स्वच्छता की राष्ट्रीय पहल 'प्रगति-50' में रायपुर और बिलासपुर क्षेत्र भी शामिल

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की महत्वाकांक्षी 'प्रगति-50' योजना में छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर को शामिल किया गया है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना का शुभारंभ किया। देश के चुनिंदा 50 शहरों में राज्य के दो शहरों के शामिल होने से मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के नगरीय विकास एवं स्वच्छता प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है।

शुभारंभ कार्यक्रम में चयनित राज्यों के नगरीय विकास विभागों, शहरी स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों ने सहभागिता की। केंद्रीय आवासन और शहरी



कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू नई दिल्ली से कार्यक्रम में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव राजनांदगांव से कार्यक्रम में वरचूअली जुड़े। मुख्यमंत्री श्री साय और उप मुख्यमंत्री श्री साव ने 'प्रगति-50' में शामिल होने पर रायपुर और बिलासपुर नगर निगमों, दोनों शहरों के स्वच्छता मित्रों तथा शहरवासियों को बधाई दी है। रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे और बिलासपुर की महापौर श्रीमती पूजा विधानी तथा दोनों नगर निगमों के आयुक्त भी कार्यक्रम में

आनलाइन सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित 51वीं 'प्रगति' बैठक के निर्देशों पर शुरू की गई यह पहल स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत चयनित शहरों में स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को तेज गति से सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। योजना में देश के 50 शहरों को शामिल किया गया है। इन शहरों को केंद्र सरकार की ओर से विशेष तकनीकी सहयोग, सतत मार्गदर्शन और गहन निगरानी मिलेगी। साथ ही

श्रेष्ठ कार्य-पद्धतियों को अपनाने के लिए भी सहयोग दिया जाएगा।

'प्रगति-50' के तहत घर-घर कचरा संग्रहण, कचरे का वैज्ञानिक पृथक्करण एवं प्रसंस्करण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। उपयोग किए गए जल के उपचार, पुनः उपयोग और समुचित प्रबंधन को बढ़ावा देने तथा नागरिकों, संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता बढ़ाने के साथ ही निर्धारित संकेतकों के आधार पर शहरों के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा एवं मॉनिटरिंग भी की जाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन में राज्य सरकार जनसुविधाओं के विस्तार, प्रभावी कचरा प्रबंधन और बेहतर सेवा-प्रदाय के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है।



श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। कभी खाली पड़ी जिस जमीन से कोई आमदनी नहीं होती थी, अब उसी जगह बायोप्लॉक तकनीक से मछली पालन कर वित्पन्न हलदर ने आय की नई राह बनाई है। मत्स्य विभाग की योजना के तहत मिली सहायता से उन्होंने बायोप्लॉक तालाब तैयार कर मछली उत्पादन शुरू किया है। वर्तमान में मछलियां बढ़वार की अवस्था में हैं और करीब तीन माह बाद बिक्री योग्य आकार में आने की उम्मीद है। इसके बाद वित्पन्न को अपने इस नए व्यवसाय से

आमदनी मिलने लगेगी।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत अपनी 'सेवा की कहानी' साझा करते हुए वित्पन्न बताते हैं कि पहले यह जमीन खाली पड़ी रहती थी और इससे किसी प्रकार का उत्पादन या आमदनी नहीं होती थी। मत्स्य विभाग से बायोप्लॉक पद्धति की जानकारी और योजना के तहत सहायता मिलने के बाद उन्होंने खाली जमीन का उपयोग मछली पालन के लिए करने का निर्णय लिया।

बायोप्लॉक तालाब निर्माण के लिए 14 लाख रुपये की इकाई लागत निर्धारित है। योजना के तहत

अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इस सहायता से हितग्राहियों को आधुनिक तकनीक से मत्स्य पालन अपनाकर स्वरोजगार और आय के नए अवसर विकसित करने में सहयोग मिल रहा है।

वित्पन्न ने भी विभागीय सहायता का लाभ लेकर मछली पालन को आजीविका के रूप में अपनाया है। वित्पन्न ने बताया कि वर्तमान में मछलियों की बिक्री योग्य आकार में आने में लगभग तीन माह का समय और लगेगा। इसके बाद तैयार मछलियों को बाजार में बेचा जाएगा। बाजार में मछली की कीमत लगभग 120 रुपये तक मिलती है। पहली खेप की बिक्री के बाद उत्पादन लागत और आमदनी के आधार पर वास्तविक लाभ का आकलन हो सकेगा। वित्पन्न को उम्मीद है कि बेहतर परिणाम मिलने पर वे इस गतिविधि को आगे भी जारी रखेंगे। योजना ने वित्पन्न के लिए खाली पड़ी जमीन के उपयोग की नई संभावना तैयार की है।

सेवा संकल्प : ब्यूटी पार्लर से किरण को प्रतिमाह 20 हजार तक की कमाई

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। कभी प्रशिक्षण के जरिए सीखा गया ब्यूटीशियन का हुनर आज श्रीमती किरण केरकेट्टा की आत्मनिर्भरता का आधार बन गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत छह माह का प्रशिक्षण लेने के बाद किरण ने छोटे स्तर पर अपना ब्यूटी पार्लर शुरू किया। धीरे-धीरे ग्राहक बढ़े और उनका हुनर नियमित आजीविका में बदल गया। आज वे अपने व्यवसाय से प्रतिमाह लगभग 12 से 20 हजार रुपये तक की आय अर्जित कर परिवार के खर्च में सहयोग कर रही हैं। इतना ही नहीं, अपने साथ दूसरे लोगों को रोजगार और प्रशिक्षण से जोड़कर उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर दे रही हैं।

अम्बिकापुर के पटेलपारा निवासी किरण केरकेट्टा बताती हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से उन्हें छह माह का ब्यूटीशियन प्रशिक्षण मिला। प्रशिक्षण के दौरान सीखे हुनर को उन्होंने स्वरोजगार से जोड़ने का निर्णय लिया और अपना छोटा सा ब्यूटी पार्लर शुरू किया। मेहनत के साथ



उनका काम आगे बढ़ा और धीरे-धीरे ग्राहक जुड़ते गए। किरण के अनुसार वर्तमान में ब्यूटी पार्लर से उन्हें प्रतिमाह लगभग 12 से 20 हजार रुपये तक की आमदनी हो जाती है। इस आय से वे परिवार की जरूरतों और घर के खर्च में सहयोग कर पा रही हैं। कौशल प्रशिक्षण से मिला हुनर उनके लिए अब केवल एक कला नहीं, बल्कि आर्थिक

आत्मनिर्भरता का माध्यम बन गया है। किरण अपनी खुशी साझा करते हुए कहती हैं, पीएम कौशल विकास के माध्यम से मुझे अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिला। छह महीने ब्यूटीशियन का कोर्स करने के बाद मैंने अपना छोटा सा ब्यूटी पार्लर शुरू किया। इससे 12 से 20 हजार रुपये तक इनकम हो जाती है और घर का खर्च भी चल जाता है।

आवा व्यक्त किया। सेवा संकल्प अभियान के तहत किरण केरकेट्टा की यह 'सेवा की कहानी' कौशल प्रशिक्षण से स्व-रोजगार और आत्मनिर्भरता तक के सफर को सागने लाती है। छह माह के प्रशिक्षण से मिले हुनर को उन्होंने अपनी मेहनत से नियमित आमदनी के साधन में बदला।

सेवा संकल्प अभियान के तहत खाद्य विभाग ने लगाया सेवा सेतु शिविर

उत्तर बस्तर कांकेर। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों को शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ सहजता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के माध्यम से सेवा सेतु शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा न्यू कम्युनिटी हॉल, कांकेर में सेवा सेतु शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कांकेर विधायक श्री अशाराम नेताम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की प्रमुख सचिव एवं जिले की प्रभारी सचिव रीना बाबासाहेब कांशले, नगरपालिका अध्यक्ष अरुण कौशल एवं जनपद अध्यक्ष श्रीमती पूर्णमा कावड़े विशेष रूप से उपस्थित रहे।

गंजेपन से मुक्ति मात्र 1 घंटे में

COMPLETE FAMILY SALON

हेयर स्प्लेसमेंट, 100% संतुष्टि की गारंटी

पहले बाद में

JATU'Z CUT N SHINE

93009-11331

रंगोली बैगल के सामने, जयसवाल इलेक्ट्रॉनिक के बाजू में इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्ग (छ.ग.)

GST NO. 22AHMPB9621P1Z2

PH.: 0748-4060131

अनुप ट्रेडर्स

आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विक्रेता

लिंक रोड, केम्प-2, पावर हाउस, भिलाई

मो. 09826389666, 8839749539



डायरेक्टर इशिका के काम की दीवानी हुई अदा खान बोलीं - मैं तो बस देखती ही रह गई

अभिनेत्री अदा खान साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज द लिफ्ट में नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ने सीरीज को लेकर अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि शूट के दौरान सभी एक्टर्स के बीच में बॉन्ड काफी अच्छा बन गया था। अभिनेत्री ने कहा, हर दिन हमारा एक नया अनुभव होता था।

एक ताजगी का एहसास था और मैं खुद भी कुछ नया महसूस कर रही थी। काफी समय से मुझे ऐसा कुछ करने का मौका नहीं मिला था। इस शो ने मुझे अलग ही खुशी दी और मुझे इस पर काम करके बहुत मजा आया। अदा खान ने सीरीज में अभिनेता प्रतीक सहजपाल के साथ काम करने को लेकर भी बात की।

उन्होंने माना कि वह खुद इंडोवर्ट हैं और जल्दी दोस्ती नहीं कर पातीं लेकिन प्रतीक ने उन्हें टीम के साथ घुलने-मिलने में मदद की। उन्होंने कहा, प्रतीक ऐसा इंसान हैं जो खुद ही माहौल को हल्का कर देता है। वह बहुत ही

चिल्ड-आउट इंसान है। आप उसके साथ बातें करते रह सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वह उन गिने-चुने लोगों में से एक है जिसके साथ मुझे खुलने में ज्यादा समय नहीं लगा। अभिनेत्री ने बताया कि वह शूट के दौरान निर्देशक इशिका के काम से भी काफी प्रभावित रही थी। उन्होंने कहा, मैं कह सकती हूँ कि मैं उनके काम से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी, या कहूँ तो मंत्रमुग्ध थी। पूरे शूट के दौरान मैं बस उनके काम को देखती रह गई।

इसके साथ ही शो की कहानी के बारे में बात करते हुए अदा ने कहा, हर इंसान में

अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। मुझे लगता है कि हर किरदार के पीछे एक साइकोलॉजिकल पहलू होता है। मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहती लेकिन हर किरदार में कई परतें हैं और उन्हें एक्सप्लोर करना काफी दिलचस्प रहा।

अदा खान ने बताया कि लिफ्ट जैसी छोटी जगह में सुबह से लेकर पैकअप तक लंबे समय तक साथ रहने से एक्टर्स को बातचीत करने, रिलैक्स करने और बॉन्डिंग करने का खूब मौका मिला, भले ही उनके सीन खत्म हो चुके हों। उन्होंने कहा कि इससे कास्ट के बीच एक बिल्कुल अलग तरह की बॉन्डिंग बनी।

रणबीर कपूर की रामायण की बदली रिलीज डेट, अब 5 नवंबर को होगी रिलीज!

रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। फिल्म के पोस्टर के बाद इसका टीजर और ट्रेलर भी जारी किया जा चुका है। फिल्म दिवाली के अवसर पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इसी बीच फिल्म की रिलीज तारीख में बदलाव की खबर सामने आई है। हालाँकि, निर्माताओं की ओर से अभी तक नई तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार, ‘रामायण: पार्ट 1’ को 6 नवंबर को रिलीज किया जाना था। हालाँकि, सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि निर्माता अब फिल्म को एक दिन पहले यानी 5 नवंबर को सिनेमाघरों में उतारने की तैयारी कर रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, निर्माताओं ने 5 नवंबर की तारीख तय कर ली है और फिल्म को दुनियाभर में एक ही दिन प्रदर्शित करने की योजना बनाई जा रही है। नई रिलीज तारीख को लेकर संबंधित पक्षों की मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है। अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद निर्माता आधिकारिक तौर पर तारीख की घोषणा कर सकते हैं। फिलहाल फिल्म की रिलीज तारीख में बदलाव को लेकर निर्माताओं की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

फिल्म की रिलीज तारीख नजदीक आने के साथ ही इसके प्रचार अभियान को भी तेज कर दिया गया है। हाल ही में फिल्म के पोस्टर का भव्य स्तर पर अनावरण किया गया। पहले पोस्टर में राम, सीता और लक्ष्मण के किरदारों की झलक दिखाई गई, जबकि दूसरे पोस्टर में रावण के रूप में यश का लुक सामने आया। फिल्म के प्रचार अभियान के बीच दर्शकों की नजर अब इस बात पर है कि ‘रामायण: पार्ट 1’ आखिर किस तारीख को सिनेमाघरों में पहुंचेगी।

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी ‘रामायण: पार्ट 1’ का निर्माण नमित मल्होत्रा ने किया है। फिल्म के प्रचार सामग्री और ट्रेलर में प्रमुख किरदारों की झलक सामने आ चुकी है। हालाँकि, हनुमान के किरदार का पूरा रूप अभी तक आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है।

अब दर्शकों की नजर फिल्म की आधिकारिक रिलीज तारीख की घोषणा पर टिकी है। यदि नई तारीख को अंतिम मंजूरी मिलती है तो ‘रामायण: पार्ट 1’ 6 नवंबर के बजाय 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज हो सकती है।

पेरिस फैशन वीक में छाई ऐश्वर्या ब्लैक गाउन में बिखेरा जलवा

बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन एक बार फिर अपने शानदार अंदाज को लेकर चर्चा बनी हुई हैं। दरअसल, एक्ट्रेस 28 सितंबर को पेरिस फैशन वीक इवेंट का हिस्सा बनीं, जहां से अब उनकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं।

ऐश्वर्या राय ने एफिल टावर के सामने प्लेस जॉर्जे में केंडल जेनर और ईवा लोंगोरिया जैसी ग्लोबल आइकन्स के साथ रैंप वॉक किया। बता दें कि इस साल शो की थीम ‘वॉक योर वर्थ’ थी, जो आत्मविश्वास, विविधता और महिलाओं की एकजुटता का जश्न मनाती है।

ब्यूटी ब्रांड की लंबे समय से ग्लोबल एंबेसडर रहीं ऐश्वर्या ने लोरियल पेरिस के ‘ले डीफिल’ के नौवें संस्करण में हिस्सा लिया। इस दौरान अभिनेत्री शाही अंदाज में नजर आईं। उन्होंने डिजाइनर यारा शुमेकर का बनाया हुआ शानदार ब्लैक वेलवेट गाउन पहना था।

अपने लुक को पूरा करने के लिए अभिनेत्री ने बालों को कर्ल किया और टियारा भी लगाया। वहीं, उन्होंने ड्यूई मेकअप और रेड लिपस्टिक के साथ अपने लुक को पूरा किया।

इस सितारों से सजे शो में ऐश्वर्या ने सिमोन ऐश्ली, वियोला डेविंस, जेन फेंडा और सेलीन डियोन सहित कई इंटरनेशनल को-एंबेसडर्स के साथ रैंप शेयर किया। शाम का एक खास पल तब देखने को



मिला, जब ऐश्वर्या और सेलीन डियोन ने एक-दूसरे का हाथ थामा, गर्मजोशी से गले मिलीं और किस किया। इसके बाद दोनों ने स्टेज पर अचानक डांस भी किया। इवेंट से एक दिन पहले अभिनेत्री फ्रांस की राजधानी पेरिस में अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ नजर आईं।

इस फिल्म में नजर आई थीं ऐश्वर्या

वहीं, ऐश्वर्या की आखिरी थिएटर रिलीज निर्देशक मणि रत्नम की फिल्म ‘पोन्निथिन सेल्वनः II’ थी। फिल्म में विक्रम, कार्थी, तृषा कृणन, जयाराम, प्रभु, आर. सरथकुमार, शोभिता धुलिपाला, ऐश्वर्या लक्ष्मी, विक्रम प्रभु, प्रकाश राज, रहमान और आर. पार्थिवन ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं।



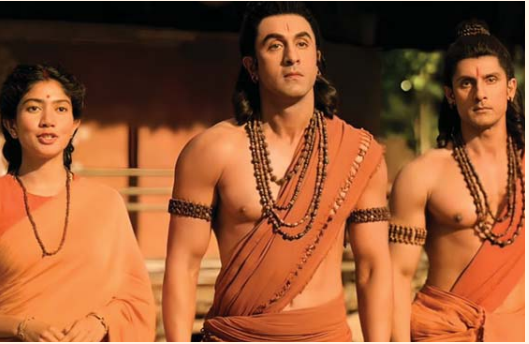
परिणीति चोपड़ा बनेंगी फील्ड रिपोर्टर, रिपोर्टिंग लाइव में खुलेगा रेत माफिया का खतरनाक खेल

अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा एक बार फिर डिजिटल माध्यम पर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। अपराध रोमांचक श्रृंखला ‘शक’ से डिजिटल दुनिया में कदम रखने वाली परिणीति अब फिल्म ‘रिपोर्टिंग लाइव’ में नजर आएंगी। फिल्म की ओटीटी प्रदर्शित होने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इसमें परिणीति एक महिला पत्रकार की भूमिका निभाती दिखाई देंगी।

ध्रुव त्रिपाठी के निर्देशन में बनी ‘रिपोर्टिंग लाइव’ एक महत्वाकांक्षी युवा पत्रकार की कहानी है। फिल्म के जरिए अवैध रेत खनन की अंधेरी दुनिया को सामने लाने का प्रयास किया गया है। कहानी में निर्दयी रेत माफिया और उससे जुड़े अपराधों के बीच पत्रकार के संघर्ष को

प्रमुखता से दिखाया जाएगा। फिल्म की कहानी पत्रकारिता, अपराध और रेत के अवैध कारोबार के इर्द-गिर्द घूमती है। परिणीति का किरदार इस पूरे आपराधिक तंत्र की पड़ताल करते हुए उससे जुड़े सच को सामने लाने की कोशिश करता नजर आएगा। ‘रिपोर्टिंग लाइव’ के जारी पोस्टर में परिणीति चोपड़ा के साथ देवेन भोजानी, अमोल पालेकर, आदिल हुसैन और शेखर सुमन भी नजर आ रहे हैं। इससे फिल्म में मजबूत सहायक कलाकारों की मौजूदगी का संकेत मिलता है।

फिल्म का निर्माण पार्थ किरण ठाकुर और जोशुआ शिरसाथ ने किया है। निर्देशन की जिम्मेदारी ध्रुव त्रिपाठी ने संभाली है। ‘रिपोर्टिंग लाइव’ का प्रदर्शन 9 अक्टूबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर किया जाएगा। डिजिटल मंच पर रिलीज होने वाली इस फिल्म में परिणीति को एक गंभीर और खोजी पत्रकार की भूमिका में देखने का मौका मिलेगा। अब दर्शकों की नजर फिल्म की कहानी और परिणीति के इस नए किरदार पर टिकी है।



केले के छिलके को खाद में बदलने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके



आमतौर पर लोग केले के छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका इस्तेमाल पौधों के लिए प्राकृतिक खाद के रूप में किया जा सकता है? केले के छिलके में पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो पौधों की वृद्धि के लिए फायदेमंद होते हैं। आइए आज हम आपको केले के छिलके को खाद में बदलने के कुछ आसान टिप्स बताते हैं।

केले के छिलकों को सुखाएं

केले के छिलके को खाद में बदलने के लिए सबसे पहले उन्हें सुखाना जरूरी है। इसके लिए केले के छिलकों को धूप में रखकर सुखाएं। इससे उनमें मौजूद नमी खत्म हो जाएगी और वे आसानी से टूटने लगेंगे। सूखे हुए छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, ताकि उन्हें खाद में मिलाना आसान हो जाए। इस प्रक्रिया से छिलकों में मौजूद पोषक तत्वों को भी बढ़ावा मिलेगा और वे पौधों के लिए अधिक फायदेमंद होंगे।

पानी में उबालें

सूखे हुए केले के टुकड़ों को पानी में उबालना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले पानी को उबालें और उसमें कटे हुए छिलकों को डाल दें।

जब पानी उबलने लगे तो आंच बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इस पानी को अपने पौधों पर डालें।

यह पानी आपके पौधों को पोषण देने में मदद करेगा और उन्हें स्वस्थ बनाए रखेगा।

भूसी बनाना

केले के छिलकों को भूसी बनाना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले सूखे हुए छिलकों को मिक्सर में पीस लें, ताकि वे बारीक पाउडर बन जाएं। इस पाउडर को आप सीधे मिट्टी में मिला सकते हैं या फिर इसे पानी में घोलकर अपने पौधों पर डाल सकते हैं। इससे आपके पौधों को प्राकृतिक तरीके से पोषण मिलेगा और वे अच्छी तरह से बढ़ भी सकेंगे।

जैविक खाद बनाना

केले के छिलकों से जैविक खाद बनाना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले सूखे हुए छिलकों को किसी बर्तन में डालें, फिर उसमें गुड़ या चीनी मिलाएं, ताकि छोटे जीवाणु सक्रिय हो सकें।

अब इस मिश्रण को कुछ दिनों तक ढककर रखें, ताकि इसमें छोटे जीवाणु विकसित हो सकें और यह खाद बन सके। जब यह मिश्रण काली मिट्टी जैसा दिखने लगे तो आपको जैविक खाद तैयार हो जाएगी, जिसे आप अपने पौधों की जड़ों में डाल सकते हैं।

प्राकृतिक खाद बनाना

प्राकृतिक खाद बनाने के लिए सबसे पहले सूखे हुए छिलकों को किसी बर्तन में डालें, फिर उसमें गुड़ या चीनी मिलाएं, ताकि छोटे जीवाणु सक्रिय हो सकें।

अब इस मिश्रण को कुछ दिनों तक ढककर रखें, ताकि यह अच्छी तरह से गल सके और खाद तैयार हो जाए। इस प्रकार आप आसानी से अपने घर पर ही केले के छिलके से प्राकृतिक खाद बना सकते हैं, जो आपके पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होगी।

ऋचा चड्ढा लेकर आई नया ट्रेवल शो मुसाफिरी दिखेगा मुंबई का अनदेखा इतिहास

अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की नॉन-फिक्शन ट्रेवल सीरीज मुसाफिरी का पहला एपिसोड रिलीज हो रहा है। इस सीरीज में मुंबई शहर के इतिहास, वहां के समुदायों, छिपी हुई कहानियों और कम चर्चित जगहों को दिखाया जाएगा। पहले एपिसोड में मुंबई के इतिहास, कल्चर और कुछ सबसे हैरान करने वाले राज दिखाए गए हैं। इस एपिसोड में किम कार्दशियन और साउथ मुंबई के सबसे मशहूर इलाकों में से एक काला घोड़ा के बीच एक अनाखा कनेक्शन भी बताया गया है। ऋचा ने मुंबई को भी एक्सप्लोर किया है और शहर के देवी-देवताओं से जुड़े दिलचस्प किस्से बताए हैं, जिनमें मां महालक्ष्मी भी शामिल हैं, जिन्हें मुंबई की माता देवी माना जाता है।

अभिनेत्री का मानना है कि मुंबई शहर ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है, जिनके बीच लोग बड़े होते हैं लेकिन कभी रुककर उन्हें जानने की कोशिश नहीं करते। अभिनेत्री ने कहा, मुंबई में इतनी सारी कहानियां हैं, जिनके बीच हम बड़े हुए हैं, लेकिन लोगों के साथ मैं इन्हें शेयर करना चाहती थीं।

एपिसोड में दर्शकों को मुंबई के सबसे पुराने आमर्नियाई चर्चों में से एक में भी ले जाया जाता है और गेटवे ऑफ इंडिया के इतिहास और इसे क्यों बनाया गया था, इसके बारे में भी बताया गया है। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जो लोग पूरी जिंदगी मुंबई में रहे हैं, वे भी शहर को एक अलग नजर से देखेंगे और उन्हें लगेगा जैसे वे एक नई मुंबई को खोज रहे हैं।

मुसाफिरी का पहला एपिसोड आज शाम उनके यूट्यूब चैनल फुलस्टॉप पर आएगा।

एक्टिंग की बात करें तो, वह आखिरी बार संजय लीला भंसाली द्वारा

निर्देशित हीरामंडी: द डायमंड बाजार में देखी गई थीं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाहौर के हीरा मंडी के रेड-लाइट एरिया पर बनी यह सीरीज ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत तवायफों के जीवन और राजनीतिक और व्यक्तिगत संघर्षों के साथ उनके जुड़ाव को दिखाती है।

सीरीज में मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा, संजीदा शेख, शर्मिन सहगल और ताहा शाह बद्शा शामिल हैं। सिनेमा में वह आखिरी बार मृगदीप सिंह लांबा द्वारा डायरेक्टेड फुकरे 3 में देखी गई थीं।



खास-खबर

कृषि मंत्री नेताम के प्रयासों से छत्तीसगढ़ के किसानों को केंद्र की बड़ी सौगात

रायपुर। राष्ट्रीय कृषि मंत्रियों के सम्मेलन ‘रबी अभियान 2026’ के अवसर पर 28-29 सितंबर को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र और किसानों के हित में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत कुल 181.99 करोड़ रुपये की द्वितीय मद की राशि जारी किए जाने की जानकारी देते हुए मंत्री रामविचार नेताम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। गौरतलब है कि कृषि मंत्री राम विचार नेताम के निरंतर प्रयासों से प्रदेश के किसानों को समृद्धि मिल रही है। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को जारी 181.99 करोड़ रुपये में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 91.20 करोड़ रुपये तथा कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत 90.79 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस राशि से राज्य में कृषि से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों को गति मिलेगी तथा किसानों को इसका लाभ प्राप्त होगा।

बाढ़ के बाद प्रभावितों के पुनर्वास पर जोर

जगदलपुर। कलेक्टर के प्रेरणा कक्ष में मंगलवार को कलेक्टर आकाश छिकारा की अध्यक्षता में समय-सीमा की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिले में विगत दिनों आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद राहत एवं पुनर्वास कार्यों की स्थिति, आगामी शासकीय आयोजनों, जनहितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन और लंबित विभागीय प्रकरणों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में वन मंडलाधिकारी दीपेश कपिल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय खन्ना, अपर कलेक्टर सीपी बघेल, नगर निगम आयुक्त प्रवीण वर्मा, सहायक कलेक्टर यशवंत नायक सहित जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी कलेक्टोरेट में उपस्थित रहे।

श्रम यशस्वी पुरस्कार के लिए 5 अवटूबर तक आवेदन आमंत्रित

गरियाबंद। श्रम विभाग द्वारा श्रम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्रमिक एवं संस्था को स्वर्गीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के तहत चयनित श्रमिक अथवा संस्था को 2 लाख रुपये की पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्रम पदाधिकारी जरती बंसल ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि में श्रम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्रमिक एवं संस्था का उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए चयन किया जाएगा। ऐसे श्रमिक अथवा संस्था, जिन्होंने श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रभावी उपाय किए हों, जिसके कारण उक्त अवधि में कोई गंभीर दुर्घटना न हुई हो तथा सुरक्षा नियमों के प्रचार-प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया हो।

रायपुर में संपत्तियों का होगा हाई-टेक ड्रोन सर्वे और GIS मैपिंग

ड्रोन सर्वे, जियो-टैगिंग और डोर-टू-डोर सत्यापन से तैयार होगा व्यापक डिजिटल एसेट डेटाबेस

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण अपनी संपत्तियों, भूखंडों, आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं तथा सार्वजनिक अधोसंरचनाओं के आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी प्रबंधन की दिशा में बड़ी तकनीकी पहल करने जा रहा है। इसके अंतर्गत प्राधिकरण के संपूर्ण अधिकार क्षेत्र में तड़स आधारित एसेट मैपिंग, हाई-टेक ड्रोन सर्वे, पुराने अभिलेखों का डिजिटलीकरण तथा डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा। परियोजना के क्रियाचयन के लिए प्राधिकरण द्वारा निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से दशकों पुराने कागजी रिकॉर्ड, संपत्ति रजिस्टर, लेजर बुक, लेआउट नक्शे तथा पट्टा और लीज से संबंधित दस्तावेजों को उच्च गुणवत्ता के साथ डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित किया जाएगा। इन अभिलेखों को मौके की वास्तविक स्थिति से जोड़ने के लिए अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक से हाई-रिजॉल्यूशन सर्वे और मैपिंग की जाएगी।

हर संपत्ति की बनेगी विशिष्ट डिजिटल पहचान: परियोजना के अंतर्गत RDA की प्रत्येक संपत्ति और भूखंड को युनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रदान किया जाएगा। UPIN संबंधित संपत्ति के



डिजिटल रिकॉर्ड और GIS मैप से जुड़ा रहेगा। इससे संपत्तियों से संबंधित जानकारी को एकीकृत और सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यवस्थित करने के साथ भविष्य में नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने का मजबूत आधार तैयार होगा।

सर्वे में केवल हवाई मैपिंग तक सीमित न रहते हुए संपत्तियों का मौके पर भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। प्रशिक्षित सर्वे टीमों द्वारा डोर-टू-डोर सर्वे किया जाएगा और मोबाइल एप के माध्यम से जियो-टैग फोटोग्राफ तथा आवश्यक संपत्ति संबंधी जानकारी डिजिटल रूप में संकलित की जाएगी। सर्वे के दौरान प्राप्त जानकारी का पुराने अभिलेखों और ड्रोन मैपिंग से मिलान किया जाएगा।

एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म भविष्य में नामांतरण, लीज नवीनीकरण, भवन अनुज्ञा और

NOC जैसी नागरिक सेवाओं को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और ऑनलाइन बनाने में सहायक होगा। संपत्ति की सीमाओं, माप और रिकॉर्ड की जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध होने से संपत्ति संबंधी विवादों के निराकरण में भी सुविधा मिलेगी।

इसके साथ ही सड़क, नाली, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट और जलापूर्ति जैसी सार्वजनिक अधोसंरचनाओं की GIS आधारित डिजिटल जानकारी उपलब्ध होने से उनके रखरखाव, मॉनिटरिंग और भविष्य की विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से तैयार किया जा सकेगा।

इस परियोजना को छह प्रमुख चरणों में आगे बढ़ाया जाएगा। पहले चरण में पुराने अभिलेखों, रजिस्ट्रों, लेजर बुक और नक्शों की स्कैनिंग एवं डिजिटलीकरण किया जाएगा। दूसरे चरण में उच्च-सटीकता वाले ड्रोन से क्षेत्र

संपत्ति प्रबंधन से नागरिक सेवाओं तक होगा फायदा

GIS आधारित डिजिटल डेटाबेस तैयार होने से RDA के पास संपत्तियों की स्थिति, सीमा, माप और उपयोग से संबंधित जानकारी अधिक व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। इससे रिकॉर्ड के सत्यापन, संपत्ति प्रबंधन और मॉनिटरिंग में सहूलियत मिलेगी। मौके की वास्तविक स्थिति और उपलब्ध अभिलेखों के तुलनात्मक अध्ययन से अनधिकृत कब्जों तथा भूमि संबंधी विसंगतियों की पहचान करने में भी सहायता मिलेगी।

तीसरे चरण में प्रशिक्षित सर्वे टीमों द्वारा डोर-टू-डोर भौतिक सत्यापन तथा चौथे चरण में मोबाइल एप से जियो-टैग फोटोग्राफ और आवश्यक संपत्ति संबंधी डेटा संकलित किया जाएगा। पांचवें चरण में पुराने अभिलेखों, ड्रोन सर्वे और भौतिक सत्यापन से प्राप्त डेटा को तद्वत प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जाएगा। अंतिम चरण में तैयार डिजिटल डेटाबेस की सुरक्षित होस्टिंग कर वेब आधारित एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपत्तियों की मॉनिटरिंग और प्रबंधन किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का हो रहा निर्माण : मुख्यमंत्री

नक्सलवाद के भय से मुक्त बस्तर के बच्चों की आंखों में अब उज्ज्वल भविष्य के सपने



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर स्थित पंडित दैनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित ‘सेवा संकल्प यात्रा एवं युवा संवाद’ कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से लंबी यात्रा तय कर रायपुर पहुंचे बाइक राइडर्स तथा बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों से पहुंचे बाइक राइडर्स को छत्तीसगढ़ की धरती पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित नए भारत का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ नागरिकों को अपना परिवार मानकर सेवा भाव से राष्ट्र निर्माण में निरंतर जुटे हुए हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाई है और आज पूरा देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सेवा संकल्प यात्रा देश की युवा शक्ति को सेवा, सामाजिक सरोकार और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का

महत्वपूर्ण माध्यम है। गुजरात के वडनगर से प्रारंभ हुई यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि से उनकी कर्मभूमि वाराणसी तक सेवा का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है। यात्रा के दौरान युवा स्वच्छता, नशामुक्ति, टीबी मुक्त भारत और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर समाज को जागरूक कर रही हैं। यह यात्रा युवाओं में राष्ट्र के प्रति दायित्वबोध और सेवा की भावना को और मजबूत कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर छत्तीसगढ़ में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत डेढ़ करोड़ से अधिक दीप प्रज्वलित किए गए। प्रदेशवासियों ने जिस उत्साह और आत्मीयता के साथ इसमें

सहभागिता की, वह प्रधानमंत्री के प्रति जनता के स्नेह और विश्वास को अभिव्यक्त करता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ से गहरा और आत्मीय संबंध रहा है। उन्होंने प्रदेश में लंबा समय बिताया है और यहां के जनजीवन को निकटता से देखा और समझा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्रीय राज्यमंत्री के रूप में उन्हें प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ कार्य करने का अवसर मिला। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की कार्यशैली, अनुशासन, दूरदृष्टि और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण को करीब से देखा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का

लक्ष्य देश के सामने रखा है। इसी लक्ष्य के अनुरूप छत्तीसगढ़ भी विकसित राज्य बनने की दिशा में योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर भविष्य की आवश्यकताओं और संभावनाओं के अनुरूप कार्ययोजना बनाई है। शासन की प्राथमिकता है कि विकास का लाभ प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर में आए बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि कभी हिंसा और भय से प्रभावित रहे क्षेत्रों में अब शांति, विश्वास और विकास का वातावरण मजबूत हुआ है। दूरस्थ अंचलों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। बदलते बस्तर में आज नई पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर बड़े सपने देख रही है।

कार्यक्रम के दौरान आयोजित युवा संवाद में बस्तर से आकर रायपुर के विद्यालयों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों गोविंद कुमार, दृष्टि ध्रुव, दीपक मरकाम और दीना उड्के ने अपने अनुभव साझा किए। विद्यार्थियों ने बस्तर में आए बदलाव पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि अब बस्तर के दूरस्थ

क्षेत्रों में भी स्कूल, अस्पताल और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है तथा भय का वातावरण समाप्त होने से बच्चों और युवाओं में भविष्य को लेकर नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है।

विद्यार्थियों ने कहा कि बस्तर की नई पीढ़ी अब भारतीय सेना और सिविल सेवाओं में शामिल होने के साथ डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़कर देश एवं प्रदेश की सेवा करने के सपने देख रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने विद्यार्थियों के विचारों की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर के बच्चों की आंखों में दिखाई दे रहे ये सपने बदलते छत्तीसगढ़ की सबसे सुखद तस्वीर हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें।

कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन करते हुए राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने सेवा संकल्प यात्रा की जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा के अंतर्गत 1200 युवा लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान युवाओं द्वारा स्वच्छता, टीबी मुक्त भारत, नशामुक्ति और पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न सामाजिक विषयों पर जनजागरूकता का संदेश दिया जा रहा है।

अब घर बैठे 1-विलक में कराएं जमीन का सीमांकन तहसील दफ्तरों के चक्करों से मिली आजादी

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राज्य में नागरिक सुविधाओं को सुगम, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। प्रदेश के राज्यस् एवं भू-अभिलेख विभाग ने जमीन के सीमांकन संबंधी प्रकरणों के त्वरित और सहज निपटारे के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर लागू कर दिया है।

इस आधुनिक व्यवस्था के शुरू होने से अब आम नागरिकों को अपनी ही जमीन की नाप-जोख या सीमांकन कराने के लिए तहसील कार्यालयों के बार-बार चक्कर काटने की पसबूरी से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। घर अथवा नजदीकी केंद्र से ही सीमांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेगा। पुरानी व्यवस्था के तहत जमीन का सीमांकन कराने के लिए

आवेदकों को खुद तहसील दफ्तर जाकर आवेदन जमा करना पड़ता था। इतना ही नहीं, आवेदन के बाद फाइल किस स्तर पर अटकती है, कार्रवाई पूरी होने में देरी क्यों हो रही है या किन कारणों से मामला लंबित है-इसकी सही जानकारी समय पर न मिल पाने के कारण लोगों को हफ्तों और महीनों तक दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। नवीन व्यवस्था ने इस पूरी जटिल प्रक्रिया को बेहद सुलभ बना दिया है। लोक सेवा केंद्र सेवा सेतु या फिर राज्यस् विभाग के सिटीजन पोर्टल के माध्यम से सीधे ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। कोई आवेदक ऑनलाइन या फिर राज्यस् विभाग के सिटीजन पोर्टल के माध्यम से सीधे ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। कोई आवेदक ऑनलाइन या फिर राज्यस् विभाग के सिटीजन पोर्टल के माध्यम से सीधे ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। कोई आवेदक ऑनलाइन या फिर राज्यस् विभाग के सिटीजन पोर्टल के माध्यम से सीधे ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

सांसद बघेल ने 2 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई, क्षेत्र के विकास पर दिया जोर

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई नगर द्वारा नेहरू भवन, सुपेला में आयोजित ‘प्रेस से मिलिए’ कार्यक्रम में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल भिलाई के पत्रकारों से रू-बर-रू हुए।

इस दौरान उन्होंने भिलाई की पत्रकार बिरादरी के बीच अपने इस बार के संसदीय कार्यकाल के 2 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। सांसद विजय बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। साथ ही आने वाले दिनों में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के विकास का विजन भी बताया।

इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद



विजय बघेल द्वारा मां सरस्वती के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनिल गुप्ता, महासचिव दिलीप शर्मा सहित प्रेस क्लब के अन्य सदस्यों ने सांसद का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। इसके बाद अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। प्रेसक्लब के उन्नयन और महत्वपूर्ण सामग्री के लिए अध्यक्ष ने सांसद बघेल को एक मांगपत्र भी सौंपा। मांगपत्र पर सांसद ने सकारात्मक प्रयास करने

का आश्वासन दिया। पत्रकारों की संबोधित करते हुए सांसद विजय बघेल ने कहा कि पत्रकार समाज की घटनाओं और जनसमस्याओं को प्रामाणिकता के साथ सामने लाने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र एक व्यपक क्षेत्र है, जिसमें चार नगर निगमों सहित शहरी और ग्रामीण दोनों अंचल शामिल हैं। केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि और प्रशासन मिलकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सांसद ने बताया कि भिलाई औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां श्रमिकों की सुविधाओं, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

प्रतापपुर में नि:शुल्क आयुष शिविर

सूरजपुर । सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिला आयुष अधिकारी सूरजपुर के मार्गदर्शन में प्रतापपुर के न्यू बस स्टैंड स्थित मंगल भवन में ब्लॉक स्तरीय नि:शुल्क आयुष स्वास्थ्य एवं जनजागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष चन्द्रमणि पैकारा की उपस्थिति में शिविर का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर अन्य जनप्रतिनिधि, महाविद्यालय के प्राचार्य, खंड चिकित्सा अधिकारी प्रतापपुर, आरोप्य भारती के पदाधिकारी, शिक्षक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक उपस्थित थे। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने लोगों की स्वास्थ्य जांच कर आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से उपचार एवं परामर्श दिया। कुल 275 रोगियों को सेवाएं प्रदान की गयी परामर्श के बाद आवश्यक औषधियों का नि:शुल्क वितरण भी किया गया।

SAIRAM
Mobile Accessories

मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़कों की आवश्यकता है

7000415602

Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

चौरसिया ज्वेलर्स

आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता

बेन्वेक्स एवं प्रहलत उपलब्ध यहां उचित व्याज दर पर धरवी रखी जाती है

मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई

9827938211, 9827171332

CAR DECOR

House Of Exclusive Seat Cover, Car Stereos Matting & Sun Control Film & Other Accessories

Shop No.3 Nafish Tower, Opp. Indian Coffee House, Akashganga, Bhilai

Mo.9300771925, 0788-4030919

K. Satyanarayan

ROCKEY INDUSTRIES FURNITURE PALACE

Deals in: (Steel & Wooden) Luxury & Imported Furniture

Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 22964330

Shri Vijay Enterprises

Sanitarywares, Tiles, CPVC Pipes & Bathroom Fittings etc.

Supela Market, Bhilai

PH. 0788-4030909, 2295573

खास खबर

नाबालिग से रेप, युवक को 20 साल की सजा

रायपुर राजधानी रायपुर के खमतलाई थाना क्षेत्र में 13 साल 11 महीने की लड़की से रेप के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी मुनेंद्र ध्रुव को दोषी ठहराते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता कक्षा 6वीं की छात्रा थी। प्रथम फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज अच्छलाल काछी ने यह सजा सुनाई। पीड़िता की ओर से विशेष लोक अभियोजक डालेश्वर साहू ने पेरवी को 10 दिसंबर 2025 की शाम करीब 7 बजे नाबालिग घर से बिना बताए चली गई थी। परिवार ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। पुलिस ने गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। 12 दिसंबर को नाबालिग अपनी मां के साथ थाने पहुंची। पुलिस ने उसका बरामदगी पंचनामा तैयार किया। इसके बाद 13 दिसंबर को उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। कोर्ट ने पीड़िता को हुई शारीरिक और मानसिक क्षति के साथ पुनर्वास को देखते हुए 5 लाख रुपए प्रतिकर देने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर से की है। कोर्ट ने साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया।

सेप्टिक टैंक कांड का आरोपी अबिकापुर से गिरफ्तार

कोरबा। श्यांग पुलिस ने लगातार खोजबीन के बाद सेप्टिक टैंक कांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने चरित्र संदेह के चलते लिव इन में रह रही महिला की हत्या कर शव को सेप्टिक टैंक में ठिकाने लगा दिया, जब परिजनों ने मृत्तिका की तलाश तेज कर दी तो वह घर में ताला जड़कर फरार हो गया। वह अलग अलग शहरों में घूमते हुए अबिकापुर के लेबर सप्लायर के घर पहुंचा, पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई उपरांत आरोपी को जेल धातलकर पकड़ लिया है। घटना श्यांग थानांतर्गत ग्राम बरपाली में 27 अगस्त को घटित हुई थी। यहां रहने वाले मनोज उरांव 40 वर्ष की जान पहचान बेवा संतोषी 33 वर्ष से हुई। पूछताछ करने पर चरित्र संदेह के चलते महिला की हत्या करने व शव को ठिकाने लगाने की बात स्वीकार किया है। मामले में पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई उपरांत आरोपी को जेल दाखिल करा दिया है।

सरपंच के घर से सागौन की अवैध सिंझियों का जखीरा बरामद

गंडईपंडरिया। वनांचल क्षेत्र पैलीमेटा में वन विभाग ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सरपंच के घर समेत दो ठिकानों पर दबिश दी। विभाग को पैलीमेटा क्षेत्र में अवैध रूप से लकड़ी के भंडारण को सूचना मिली थी। तलाशी के दौरान परिसर में रखे सागौन के लट्टे और तख्ते बरामद हुए। विभाग के अनुसार लकड़ी के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। जंगल से कटाई और कारोबार की जांच वन विभाग ने बरामद लकड़ी को जप्त कर लिया है। मामले में वन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर संबंधित लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।

शराब के विवाद में नाबालिग की हत्या, लकड़ी के छिलके से सिर पर किया वार, आरोपी गिरफ्तार



श्रीकंचनपथ न्यूज

दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिले में शराब को लेकर हुए विवाद में एक शख्स ने नाबालिग के सिर पर लकड़ी के छिलके से वार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के करीब 12 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल लकड़ी का छिलका भी बरामद किया गया है। मामला बारसूर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, हितामेटा राऊतपारा निवासी नाबालिग 27 सितंबर की शाम करीब 8 बजे घर से गांव में घूमने निकला था। रात करीब 8 बजे वह बुधराम पोडियामी (44) के घर पहुंचा। यहां शराब को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर बुधराम ने लकड़ी के छिलके से नाबालिग के सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलने के

झांकी देखने उमड़े 5 लाख लोग : 2 हजार पुलिस तैनात 2250 से ज्यादा कड़े, 30 से ज्यादा चाकू व कैंची जब्त

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर में गणेश विसर्जन और झांकियों के दौरान हर साल होने वाली चाकूबाजी की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पुलिस ने इस बार गणेशोत्सव शुरू होते ही चाकूबाजों पर सख्ती शुरू कर दी थी। हर थाने में विशेष अभियान चलाया गया और क्राइम ब्रांच को अलग टास्क दिया गया। झांकी रूट में प्रवेश करने वाले हर

व्यक्ति की जांच का फैसला लिया गया। झांकी वाली रात 9 बजे से तलाशी शुरू हुई तो चाकू-कैंची के साथ एक खोफनाक पैटर्न सामने आया। बड़ी संख्या में युवक साइकिल की चेन वाले चक्के जैसे आकार के नुकीले कड़े पहनकर झांकी में पहुंच रहे थे। तलाशी में 2250 से ज्यादा ऐसे कड़े और 30 से ज्यादा चाकू-कैंची बरामद हुए। कई लोग शराब की बोतल लेकर झांकी में पहुंचे थे। ऐसे 55 से ज्यादा लोगों को



गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि कमिश्नरी लागू होने के बाद 25 साल में पहली बार झांकी के दौरान चाकूबाजी की घटना नहीं हुई। इस बार झांकियां देखने 5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। पुलिस-प्रशासन के अनुसार पिछले साल के मुकाबले भीड़ 35 से 40 फीसदी ज्यादा थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 15 से ज्यादा चोरी के वाहन बरामद किए। चाकू और अन्य आपत्तिजनक सामान

के साथ मिले संदिग्धों को संबंधित थानों को सौंपा गया। भीड़ से एंबुलेंस को निकाला: जयसंथ चौक पर मरीज लेकर पहुंची एंबुलेंस भीड़ में फंस गई। पुलिस व लोगों ने रास्ता बनाकर बाहर निकाला। दो माह पहले से तैयारी: सुरक्षा की तैयारी दो माह पहले शुरू हुई। रोज करीब 800 पुलिसकर्मी तैनात रहे। ड्रोन, आईटीएमएस और सीसीटीवी से निगरानी की गई।

पुलिस की बड़ी कार्रवाई : कमीशन के लालच में बैंक खातों का दुरुपयोग, 14 आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार साइबर अपराध एवं म्यूल बैंक खातों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना छावनी, थाना नेवई एवं एसीसीयू की टीम ने 14 म्यूल खाताधारकों पर कार्रवाई की। जांच में साइबर टीम की रकम के लेन-देन में इन खातों का उपयोग किया गया। नेवई थाना क्षेत्र से 11 व छावनी थाना क्षेत्र से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफथाना छावनी में धारा 318(2), 318(3), 317(4) बीएनएस तथा थाना नेवई में धारा 318(2), 318(3), 317(4) के तहत कार्रवाई की गई।

साइबर अपराधों की विवेचना के दौरान प्राप्त तकनीकी साक्ष्यों एवं बैंक खातों के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया कि कुछ खाताधारकों द्वारा कमीशन/प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने बैंक खाते अथवा बैंक खाते से संबंधित पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक एवं सिम कार्ड अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गए थे। इन खातों का उपयोग साइबर टीम से प्राप्त धनराशि के विभिन्न खातों में अंतरण एवं लेन-देन के लिए किया गया। विवेचना के दौरान संबंधित खाताधारकों एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों से यह भी ज्ञात हुआ कि आरोपियों द्वारा कमीशन के लालच में अपने अथवा अन्य व्यक्तियों के बैंक खाते,



पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक एवं सिम कार्ड एजेंट/अन्य व्यक्तियों के माध्यम से साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराए जाते थे। बैंक खातों को लगभग 2,000 से 15,000 तक के कमीशन के बदले उपलब्ध कराया गया था। संबंधित खातों में साइबर टीम से प्राप्त धनराशि के करोड़ों रुपये से अधिक के संदिग्ध लेन-देन होना पाया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर थाना नेवई में 11 एवं थाना छावनी में 3 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरणों में वैधानिक कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई में थाना छावनी, थाना नेवई एवं एसीसीयू में पदस्थ पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने बैंक खातों के तकनीकी विश्लेषण, संदिग्ध लेन-देन की जांच एवं उपलब्ध साक्ष्यों

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

कार्तिक बाग, उम्र 27 वर्ष, निवासी बजरंग चौक, रूआबांधा, भिलाई, थाना भिलाई नगर, बबलू शाह, उम्र 26 वर्ष, निवासी संजय नगर, आदर्श पारा, सुपेला, थाना सुपेला, बलवंत सिंह, उम्र 22 वर्ष, निवासी न्यू कृष्णा नगर, धनवंतरी स्कूल के पीछे, सुपेला, थाना सुपेला, समीर साहनी, उम्र 19 वर्ष, निवासी एचपीसीएल कॉलोनी, 138 डी, रूआबांधा, थाना भिलाई नगर, चन्द्रप्रकाश पाटक, उम्र 28 वर्ष, निवासी श्रमिक नगर, छावनी, थाना छावनी, यतेन्द्र धनकर, उम्र 37 वर्ष, निवासी 8 बी, सड़क क्रमांक 10, सेक्टर, भिलाई, थाना भिलाई नगर, गुरजीत सिंह रंधावा, उम्र 22 वर्ष, निवासी कैम्प-1, भिलाई, थाना छावनी, राकेश सेन, उम्र 34 वर्ष, निवासी श्याम नगर, लिंक रोड, भिलाई, थाना छावनी, राकेश देवागन, उम्र 44 वर्ष, निवासी भाटापारा, कुरुद, थाना जामुल, फैजल खान, उम्र 19 वर्ष, निवासी रूआबांधा गांधी चौक, थाना भिलाई नगर, रीता कुमारी, निवासी उडिया बस्ती, खुसीपार, थाना खुसीपार, रवि भारती, उम्र 29 वर्ष, निवासी कदम कैपिटल, अंजोरा, थाना पुलगांव, रविन्द्र साहू, उम्र 66 वर्ष, निवासी सेक्टर-6, सड़क क्रमांक 40, कार्टर नंबर 40, भिलाई, थाना भिलाई नगर, सुजीत सिंह, उम्र 39 वर्ष, निवासी कैम्प-1, सुभाष चौक, 165/एफ, भिलाई, थाना छावनी।

घरों में छिपाकर रखे थे तलवार-चापड़ और एयरगन गुंडा-बदमाश समेत 4 गिरफ्तार, बैंक दस्तावेज भी मिले

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। दुर्ग के वैशाली नगर थाना पुलिस ने कैप-1 में कार्रवाई करते हुए घोषित गुंडा-बदमाश समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 11 हथियार मिले हैं। इनमें एयरगन, बड़ी और छोटी तलवार, लोहे की तलवार, चापड़, खुखरी और बटन्दार धारदार हथियार शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, किसी भी हथियार का वैध दस्तावेज नहीं मिला। कार्रवाई 28 सितंबर को की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हैं। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और चारों को पकड़कर तलाशी ली। इस दौरान हथियारों के अलावा 2 लाख 97 हजार 650 रुपए कैश, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और



मुबाइल फोन भी मिले। पुलिस के मुताबिक, बरामद हथियारों में एक एयरगन, एक बड़ी तलवार, एक छोटी तलवार और दो लोहे की तलवार शामिल हैं। इसके अलावा दो चापड़, एक खुखरी, एक साधारण धारदार हथियार और एक बटन्दार धारदार हथियार मिला है। पुलिस ने सभी हथियार जब्त कर आयुध अधिनियम के तहत अलग मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में

सिम्मी उर्फ आलोक उर्फ आलू (26), इरनजीत कौर उर्फ पूजा (23), रंजीता कौर (45) और सिमरन कौर (27) शामिल हैं। इनमें सिम्मी उर्फ आलोक उर्फ आलू को पुलिस ने घोषित गुंडा-बदमाश बताया है। चारों आरोपी कैप-1 क्षेत्र के रहने वाले हैं।

न्यूल खाते के मामले में भी कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक, आरोपी दूसरे लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल संदिग्ध पैसें के लेन-देन के लिए कर रहे थे। जन्त मुबाइल और बैंकिंग दस्तावेजों की जांच से लेन-देन से जुड़ी और जानकारी सामने आने की उम्मीद है। पुलिस ने पैसें के लेन-देन के मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2), 317(4) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।

13 मवेशियों की तस्करी करते एक आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। रायगढ़ जिले में मवेशी तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन शंखनाद के तहत लैलूंगा पुलिस ने पिकअप से मवेशियों की तस्करी कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 13 गौवंशों को पिकअप में टूसकर झारखंड-ओडिशा की ओर ले जा रहा था। पुलिस ने मवेशियों और पिकअप समेत करीब 11 लाख 4 हजार रुपए की संपत्ति जब्त की है।

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि, सफेद रंग की पिकअप में काला पनी ढककर मवेशियों को क्रूरतापूर्वक भरकर झारखंड-ओडिशा की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने ग्राम कुंजारा मेन रोड पर घेराबंदी की। इसी दौरान घरघोड़ा की ओर से आती सफेद पिकअप को रोककर तलाशी ली गई। वाहन में 13 गौवंश मिले। सभी को टूसकर रखा गया था। पुलिस ने वाहन ड्राइवर से मवेशियों के परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे। ड्राइवर इमरान खान (29), निवासी केराडिह, थाना नारायणपुर, जिला जशपुर पहले टालमटोल करता रहा। बाद में वह कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका। पूछताछ में उसने



मवेशियों को झारखंड-ओडिशा की ओर बूचड़खाने ले जाने की बात बताई। गौवंशों की अनुमानित कीमत 1 लाख 4 हजार रुपए और पिकअप की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई गई है। इस तरह कुल 11 लाख 4 हजार रुपए की संपत्ति जब्त की गई। मुक्त कराए गए गौवंशों को ग्राम झरन की गौशाला में चारा-पानी के साथ सुरक्षित रखा गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफछत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6, 10 और 11 के तहत अपराध दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

ब्याज के पैसे नहीं देने पर दंपती ने काटा गला 6000 की उधारी पर मांगा 18 हजार ब्याज

बिलासपुर। बिलासपुर में ब्याज की रकम को लेकर हुए विवाद के दौरान पति-पत्नी ने मिलकर युवक का गला काट दिया, जिससे गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देवरीडीह के देवनगर निवासी सरिता साहू ने पुलिस को बताया कि करीब दो साल पहले घरेलू काम के लिए उसने तहरून निशा से 6 हजार रुपए उधार लिए थे। जिसके मूलधन की राशि वह चुका चुकी हैं। इसके बावजूद 27 सितंबर की रात करीब 8 बजे तहरून निशा और उसका दूसरा पति राजू पटान घर पहुंचे और 18 हजार रुपए ब्याज बकाना होने की बात कहकर विवाद करने लगे। इस दौरान सरिता ने उनसे मोहलत मांगी, तो दोनों पति-पत्नी घर लौट गए। जिसके बाद रात करीब 11 बजे दोनों फिर पहुंचे और दरवाजा खटखटाने लगे। बाहर आने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी। विरोध करने पर राजू पटान ने नुकीले धारदार हथियार से अनिल साहू के गले और दोनों कलाई पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंची सरिता से भी धक्का-मुक्की की गई। इस हमले में गंभीर रूप से घायल अनिल साहू इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। उसकी पत्नी सरिता ने मामले की शिकायत पुलिस से की। युवक के गले और कलाई में गहरा जख्म लगा है। लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित का कहना है कि उनकी शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई करने की भी बात कही है।

Ashok JEWELLERY

Gifts • Toys • Cosmetics
Perfumes • Sisa Jewellery

Beside Parakh Jewellers,
Akash Gangra,
Supela, Bhilai

Hello: 0788-4052727

Mukesh Jain 9009959111
Rishabh Jain 8103831329

// न्यायालय तहसीलदार तहसील भिंभीरी, जिला-बेमेतरा (छ.ग.) //

// इशतहार //

क्रमांक / 229 /ना. तह / 2026

भिभीरी दिनांक 15.09.2026

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचनायें प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री रमेश पिता धनौराम निवासी ग्राम खुड़मुड़ी तहसील तहसील भिभीरी जिला बेमेतरा द्वारा जो कि वह अपने माता स्व. श्रीमती कान्ताई पति धनौराम की दिनांक मृत्यु दिनांक 18.09.2012 को ग्राम खुड़मुड़ी में मृत्यु हो जाने से मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने से मृत्यु प्रमाण पत्र बनावये जाने आवेदन पत्र आधार कार्ड की प्रति, 20/- रु चालान की प्रति, कार्यालय जिला रजिस्ट्रार सचिव (जन्म-मृत्यु) ग्राम कुन्ही जिला बेमेतरा द्वारा जारी अनुपलब्धता प्रमाण पत्र पेश किया गया। जो प्रकरण इस न्यायालय में विचारधीन है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति / संस्था को दावा / आपत्ति करना हो तो वह दिनांक 30.09.2026 को स्वयं या किसी अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा आवेदन पेश कर सकते हैं। निवत दिनांक बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईशतहार भरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 15.09.2026 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार
भिंभीरी, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड-बेमेतरा (छ.ग.)

Phone No. : 07824-222118 email : eebem-phe-cg@nic.in

निआसू.क्र 07 / तशा / का.अ. / लो.स्वा.यां.खंड / 2026-27 बेमेतरा, दिनांक 28.09.2026

मैनुअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों से प्रपत्र 'ए' में निम्नांकित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	विकास खण्ड	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु.लाख में)
1	बेमेतरा	जिला खनिज संस्थान न्यास मद योजनांतर्गत बेमेतरा जिले के विकासखंड बेमेतरा के ग्राम उमरिया में 90 mm 10Kg/cm2 UPVC Pipe पाईप लाईन प्रदाय कर जोड़ने, बिछाने, इन्टरकनेक्शन स्पेशलिस्ट सहित विद्युत कनेक्शन, सबमर्सिबल पंप संबंधी समस्त कार्य, टेस्टिंग 02 माह का ट्रायल रन, संचालन एवं संधारण का कार्य। (सम्पूर्ण कार्य सामग्री सहित)	8.20

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 12.10.2026 संस्था 5.30 बजे तक है तथा अघोस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में भरे हुए निविदा प्रपत्र दिनांक 26.10.2026 को संस्था 5.30 बजे तक स्पीड पोस्ट द्वारा स्वीकार किये जा सकेंगे। उपरोक्त कार्य की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज, निविदा का विस्तृत विवरण व अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट https://phed.cg.nic.in/project/niiv में दिनांक 12.10.2026 को संस्था 10.00 बजे तक देखी जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बेमेतरा (छ.ग.)

जी-262703602/2

भिलाई की सबसे बड़ी चुड़ी की दुकान

निखार बैंगल

मो.- 9826186026

Shop-47, 'A' Market, Sec-6, Bhilai Nagar, Distt., Durg (C.G.)

भिलाई मसाला उद्योग

शुद्ध कुटे हुए मसाले, पापड़, अचार, बड़ी, जड़ी-बूटी, जचकी का सामान इत्यादि

128, ए- मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई, फोन. 2284508, मो. 9826137766

खास-खबर

**किसान की बेटी मनीषा बनेगी डॉक्टर, नीट में मिली सफलता**

रायपुर। बस्तर जिले के दरभा विकासखंड स्थित ग्राम छिंदावाड़ा-कावाराम की होनहार बेटी मनीषा कश्यप ने अपनी मेहनत के बल पर नीट-2026 में शानदार सफलता अर्जित कर सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट पक्की कर ली है। एक साधारण कृषक परिवार से ताल्लुक रखने वाली मनीषा अपने गांव से डॉक्टर बनने की दिशा में कदम बढ़ाने वाली पहली छात्रा बन गई हैं।

आपराधिक गतिविधियों के लिए समीक्षा प्राधिकरण का गठन

रायपुर। गृह विभाग ने विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत जांच के दौरान एकत्रित साक्ष्यों की स्वतंत्र समीक्षा तथा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में राज्य सरकार को अनुसंसा करने के लिए गठित समीक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति की है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश गौतम चौरड़िया को समीक्षा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 45 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है।

सितंबर का खाद्यान्न वितरण अब 15 अक्टूबर तक

रायपुर। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह सितंबर एवं अक्टूबर 2026 के लिए खाद्यान्न का अंबटन जारी कर दिया गया है। खाद्य विभाग के अनुसार 29 सितंबर तक राज्य के 71 लाख राशन कार्डधारियों को सितंबर का 90 प्रतिशत चावल वितरित किया जा चुका है। शेष राशनकार्डधारियों को भी खाद्यान्न वितरण का कार्य निरंतर जारी है।

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के लिए 130 हूप शार्टलिस्ट, 8 अक्टूबर को प्लेयर ड्राफ्ट

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के पहले सीजन के लिए आयोजित दो दिवसीय चयन ट्रायल आज रायपुर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में संपन्न हुआ। ट्रायल के लिए कुल 373 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 223 खिलाड़ियों ने भाग लिया। दो दिवसीय चयन प्रक्रिया और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के बाद 130 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए खिलाड़ियों ने चयन ट्रायल में हिस्सा लिया और लीग के पहले सीजन में जगह बनाने के लिए अपना दमखम दिखाया। चयन प्रक्रिया के दौरान खिलाड़ियों के खेल कौशल, प्रदर्शन और निर्धारित मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया गया।



खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव लगातार दूसरे दिन ट्रायल स्थल पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि निरंतर अभ्यास और मेहनत के माध्यम से अपने खेल को बेहतर बनाते रहें।

श्री साव ने कहा, छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के लिए आयोजित चयन ट्रायल में 373 खिलाड़ियों का पंजीकरण और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से खिलाड़ियों की भागीदारी यह दर्शाती है कि राज्य

बढ़ने के अवसर मिलें। उन्होंने शॉर्टलिस्टेड खिलाड़ियों को ड्राफ्ट और लीग के लिए शुभकामनाएँ दीं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक आकांक्षा शिखा खलखो, छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव और सचिव फिरोज अंसारी भी इस दौरान मौजूद थे।

फ्रेंचाइजी टीमों इनमें से चुनेगी अपने लिए खिलाड़ी

चयन ट्रायल के बाद अब लीग के पहले सीजन के लिए टीम गठन की दिशा में अगला महत्वपूर्ण चरण सीएचएल प्लेयर ड्राफ्ट होगा। 8 अक्टूबर को रायपुर में आयोजित होने वाले इस ड्राफ्ट में शॉर्टलिस्ट किए गए 130 खिलाड़ी शामिल होंगे। इन खिलाड़ियों में से छह फ्रेंचाइजी टीमों अपने-अपने खिलाड़ी दल का चयन करेंगी। इसके बाद लीग के पहले सीजन के लिए टीमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान

युवा शक्ति, नवाचार और स्टार्टअप्स की भागीदारी से साकार होगा विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प

श्रीकंचनपथ समाचार



रायपुर। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में युवाओं, नवाचारकर्ताओं और स्टार्टअप्स की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राज्य सरकार युवाओं के विचारों को नवाचार और नवाचार को सफल उद्यम में बदलने के लिए आवश्यक वातावरण, अधोसंरचना, तकनीकी सहयोग और प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 'युथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्वलेव-2026' को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज का युवा नए अवसर गढ़ने का सामर्थ्य रखता है। सरकार का दायित्व है कि उसके विचार को सही मंच, तकनीकी सहयोग, वित्तीय सहायता और अनुकूल नीतिगत वातावरण मिले। इसी सोच के साथ राज्य में स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। श्री साय ने कहा कि प्रदेश के बेटे-बेटियों को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए 'मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण योजना' पर काम किया जा रहा है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सहित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति-2024 में भी नए उद्यमियों के लिए अनेक प्रोत्साहन रखे गए हैं। महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजनों सहित विभिन्न वर्गों की उद्यमिता को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर अधिक रोजगार सृजित करने वाले उद्योगों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने युवाओं से कहा कि वे नई औद्योगिक नीति का गंभीरता से अध्ययन करें और उसमें उपलब्ध अवसरों का अधिकतम लाभ उठाएं।

प्रदेश में नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। सिंगल विंडो सिस्टम से प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, ताकि निवेशकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद प्रदेश को अब तक लगभग 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अनेक परियोजनाओं पर धरातल पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है।

छत्तीसगढ़ में अब परंपरागत उद्योगों

के साथ-साथ ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल और अन्य उभरते क्षेत्रों में भी निवेश को संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। प्रदेश की प्राकृतिक संपदा, ऊर्जा क्षमता, देश के मध्य में स्थित भौगोलिक स्थिति तथा लगातार मजबूत हो रही सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी निवेश और उद्यमिता के लिए छत्तीसगढ़ की संभावनाओं को और सशक्त बना रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वे किसान परिवार से आते हैं और स्वयं

विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में युवाओं की होगी निर्णायक भागीदारी

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प देश के सामने रखा है। इसी संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ भी विकसित राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2047 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लगभग 75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य केवल सरकार के प्रयासों से नहीं, बल्कि प्रदेश के युवाओं, किसानों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों,

शोधार्थियों और प्रत्येक नागरिक की भागीदारी से पूरा होगा। विशेष रूप से नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन और



एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में आगे आना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर-विशाखापट्टनम सहित महत्वपूर्ण मार्गों और अन्य कनेक्टिविटी परियोजनाओं के विस्तार से छत्तीसगढ़ की देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों तक पहुंच और बेहतर होगी। इसका सीधा लाभ उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में मिलेगा।

छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण विधेयक पर जनता से मांगें सुझाव

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग की ड्राफ्ट कमेटी द्वारा छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण विधेयक, 2026 का प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया है। प्रस्तावित विधेयक को लेकर राज्य के आम नागरिकों, विशेषज्ञों और संबंधित हितधारकों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।

गृह विभाग की ड्राफ्ट कमेटी द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 में आवश्यक संशोधन करते हुए नए विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है। आम नागरिक प्रस्तावित प्रावधानों का अध्ययन कर अपनी राय शासन के समक्ष रख सकें, इसके लिए विधेयक का प्रारूप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। प्रस्तावित विधेयक के प्रावधानों पर यदि किसी नागरिक, संस्था अथवा संबंधित हितधारक कोई सुझाव या आपत्ति दर्ज कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत शासन को भेजा जा सकता है। राज्य शासन ने प्रस्तावित विधेयक में सुझाव और आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की है।

परिवहन विभाग के कामकाज की उत्त्चस्तरीय समीक्षा

सड़क हादसों को न्यूनतम करने के लिए मिशन मोड में करें काम : मुख्यमंत्री साय

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों को न्यूनतम करने के लिए सभी संबंधित विभाग मिशन मोड में समन्वित रूप से कार्य करें।

परिवहन विभाग के कामकाज की उत्त्चस्तरीय समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सुरक्षित, सुगम और आधुनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल दुर्घटनाओं की संख्या कम करना नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली प्रत्येक संभावित जनहानि को रोकना होना चाहिए।

उन्होंने 'जीरो फेटेलिटी' के लक्ष्य की दिशा में परिवहन, पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग और नगरीय निकायों सहित सभी संबंधित विभागों को विस्तृत और परिणामोन्मुखी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान, सुरक्षित सड़क संरचना, यातायात नियमों का प्रभावी पालन, वाहनों की तकनीकी फिटनेस, प्रशिक्षित चालक और दुर्घटना के बाद त्वरित चिकित्सा सहायता जैसे सभी पहलुओं पर एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों और ब्लैक स्पॉट की पहचान कर वहां आवश्यक



सुधारात्मक एवं सुरक्षात्मक उपाय प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। बताया गया कि राज्य के 23 ब्लैक स्पॉट में सुधार की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटना होने के बाद शुरुआती समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। घायल व्यक्ति तक जितनी जल्दी सहायता और चिकित्सा सुविधा पहुंचेगी, उतनी बचाने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। उन्होंने दुर्घटना की सूचना, एम्बुलेंस की उपलब्धता, नजदीकी अस्पताल तक पहुंच और उपचार की पूरी व्यवस्था के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आम नागरिकों तक यह संदेश प्रभावी रूप से पहुंचना चाहिए कि सड़क दुर्घटना देखकर घबराएं नहीं, बल्कि पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिए आगे आए।

पीएम-राहत योजना के अंतर्गत पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ितों को दुर्घटना की तारीख से संभावित परिवहन व्यय तथा नई तकनीक आधारित परिवहन सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया।

की सुविधा का प्रावधान है। वहीं राहवीर योजना सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की समय पर सहायता करने वाले नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।

श्री साय ने ग्रामीण बस योजना को विस्तार देने के निर्देश दिए। ऐसे ग्रामीण, वनांचल और दूरस्थ क्षेत्रों को प्राथमिकता से चिन्हित किया जाए, जहां अभी नियमित सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है।

बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के अंतर्गत वर्तमान में 13 जिलों के 106 मार्गों पर 107 बसों का संचालन किया जा रहा है। कोंटा से जगरगुंडा के बीच पहली बार प्रारंभ हुई बस सेवा से क्षेत्र के नागरिकों का आवागमन में बड़ी सुविधा मिली है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश में पर्यटन विकास की संभावनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पर्यटन स्थलों तक सुरक्षित और सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित करने में परिवहन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने पर्यटन मिशन के साथ परिवहन विभाग की भूमिका को प्रभावी रूप से जोड़ने के निर्देश दिए।

बैठक में परिवहन मंत्री केदार कश्यप, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, परिवहन विभाग के सचिव एन प्रकाश, परिवहन आयुक्त डी रविशंकर, संयुक्त सचिव प्रभात मलिक सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

आज के बच्चे, कल का भविष्य

सेवा संकल्प के आंगन मिलन से साकार हो रहा सुपोषित छत्तीसगढ़



ओम प्रकाश डहरिया

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान की भावना जनभागीदारी और सेवा के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंच रही है। इस अभियान की सार्थक पहल 'आंगन मिलन उत्सव' के रूप में गांवों के आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन की सेवा-भावना से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख आधिकारिक स्तर पर भी किया गया है।

आंगन मिलन उत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बच्चों के स्वस्थ, वर्तमान और उज्ज्वल भविष्य के लिए समाज की सामूहिक जिम्मेदारी का उत्सव है। गांव के आंगनबाड़ी केंद्रों में महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों का सम्मान, बच्चों को कुपोषण से बाहर लाने में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली दीर्घायों, मितांनियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान इस पहल को सेवा और सम्मान की संवेदना से जोड़ता है।

गांव के वरिष्ठ नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता इस आयोजन को और अधिक आत्मीय बनाती है। उनके हाथों बच्चों और महिलाओं को सुपोषण एवं स्वस्थ जीवन के लिए उपयोगी टिप्स दिए जाने उस पीढ़ी के अनुभव को नई पीढ़ी के भविष्य से जोड़ने जैसा है।

उत्सव में अन्न के दानों से बनाई गई सुपोषण की रंगोली केवल कला की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि यह संदेश देती है कि हमारे घर और खेतों में उपलब्ध पौष्टिक अन्न ही स्वस्थ जीवन की मजबूत नींव है। बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी सुपोषण का संदेश सहज और प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है।

सहायक जनसंपर्क अधिकारी

मां के स्वास्थ्य, बच्चे के पोषण, परिवार की जागरूकता और समाज की सहभागिता से जुड़ा व्यापक संकल्प है। इसलिए कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता, मातृ-शिशु स्वास्थ्य की देखभाल और सुपोषण की आदतों को बढ़ावा देना वास्तव में आने वाली पीढ़ी के लिए किया गया सबसे बड़ा निवेश है। सेवा संकल्प की यही असली तस्वीर है।